सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 188, नई दिल्ली । मंगलवार, 17 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 शराब घोटाले में संलिप्तता या जेल जाने पर इस्तीफा क्यों नही दिया- देवेन्द्र यादव

06 उत्तम पालन-पोषण: अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर ध्यान देना

08 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आएंगे

एलजी सक्सेना ने दिया अल्टीमेटम, अधिकारियों ने तेजी से शुरू किया काम; दिल्ली के तीनों ISBT का हो रहा कायापलट

संजय बाटला

दिल्ली के यातायात और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए एलजी सक्सेना के निर्देश पर तेजी से काम हो रहा है। कश्मीरी गेट आनंद विहार और सराय काले खां बस अड्डों में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टैंड फीस लागू होने से बसों के ठहराव के समय में सुधार हुआ है। एलजी ने अधिकारियों को जल्द काम पूरा कराने का अल्टीमेटम दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली की यातायात व्यवस्था और यात्री सुविधाओं में हो रही लापरवाही पर एलजी की नाराजगी के बाद सुधार की दिशा में काम होता दिख रहा है। एलजी स्वयं दौरा करके यातायात व्यवस्था व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उनके इस प्रयास के बाद आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां बस अड्डे में बड़े स्तर पर सुधार और बदलाव का काम जारी है।

एलजी के निर्देश पर इन तीनों बस अड्डों में 15 सितंबर से नई स्टैंड फीस के लागू हो चुकी है जिसके बाद बसों के ठहराव के समय में सुधार और बसों के संचालन और यातायात व्यवस्था बेहतर देखी जा रही है लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अपेक्षाकृत काम नहीं हुआ है जिस पर एलजी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जल्द काम पूरा कराने का अल्टमेटम दिया है।

एलजी ने सभी आईएसबीटी का किया था दौरा

अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने 31 अगस्त को कश्मीरी गेट व नौ सितंबर को सराय काले खां और आनंद विहार का का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने वहां पर रखरखाव और यात्री संबंधित कई खामियों को उजागर किया था। उन्होंने अधिकारियों से इन समस्याओं समाधान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने यहां खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर और

सुविधाओं पर नाराजगी जताई और और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी चिंता प्रकट की थी।

तीनों आइएसबीटी के मरम्मत और रखरखाव का कार्य जारी

इसके बाद से अधिकारी इन समस्याओं का संज्ञान लेकर तीनों आइएसबीटी के मेकओवर, मरम्मत और रखरखाव के कार्यों को पूरा कराने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कश्मीरी गेट पर क्षतिग्रस्त फुटपाथ का पुनर्निर्माण किया गया है। फास्टैग के एंट्री गेट पर खराब स्थिति में मिले पोर्टा कैबिन को भी सही कर दिया गया है। फास्टैग बैरियर के पास स्टोर रूम को भी सही किया गया है।

कश्मीरी गेट में अतिक्रमण को हटाया गया

कश्मीरी गेट में दुकानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। टिकट काउंटर को अब लिंक ब्लॉक में स्थानांतरित किया गया है। वेटिंग हाल के फर्श को ठीक किया गया है। वहीं आनंद विहार बस अड्डे प्लेटफार्म ए और डीएमआरसी बाउंडरी वाल का काम प्रगति पर है। प्लेटफार्म और डीटीसी बसों के एंट्री रोड के बीच मिले गड्ढों की मरम्मत का काम चल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि यह काम एक महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

क्या मुख्यमंत्री दिल्ली अपने पद के साथ मुख्यमंत्री आवास (शीश महल) भी छोड़ेंगे ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने राजनीति जगत में एक नया संदेश और नया उदाहरण स्थापित कर देश के राज्यो मे बने हुए और बनने वाले मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को प्रदान किया है की जेल जाना भी पड़े तो पद का त्याग ना करे। जेल से जमानत पर छूटते ही जनता का ह्रदय सम्राट बनने के उद्देश्य को लेकर तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देते समय लगाई गई शर्त को नया रूप देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। अब प्रश्न यह उठता है की एक नई मिसाल सम्पूर्ण भारत के राजनीतिज्ञ को देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ मुख्यमंत्री आवास (शीश महल) का भी त्याग कर नए बनने वाले मुख्यमंत्री के लिए खाली करेंगे या शीश महल का प्रयोग आम आदमी पार्टी के सयोजक के रूप में अपने ही निवास के लिए प्रयोग करेंगे। आपकी जानकारी हेतु बता दें मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण पर पहले से ही कई दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और अभी भी औरों पर गिरने की आशा की जा रही है। अब देखना यह है की आज जैसा की उम्मीद की जा रही है की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोषणा कर अपने पद से इस्तीफा देंगे तो क्या वह साथ में ही शीश महल को छोड़ने की बात करते हैं या नहीं।

'आप' ऑटो विंग ने संवाद कर गिनाए केजरीवाल सरकार के काम

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 16 सितंबर आम आदमी पार्टी के ऑटो विंग ने सोमवार को बुराड़ी विधानसभा में ऑटो वालों के साथ संवाद किया। इस दौरान ऑटो वालों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी गई। ऑटो संवाद कार्यक्रम को बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और ''आप'' ऑटो विंग के प्रभारी गौरव सिंह ने संबोधित किया। ऑटो वालों ने केजरीवाल सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमेशा उनका ख्याल रखा। उनकी कई तरह फीस माफ कर दी और कोरोना काल के दौरान भी आर्थिक मदद की। सभी ऑटो वालों ने अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर खुशी जताई।

बुराड़ी में आयोजित ऑटो संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए कई सारे काम किए हैं। मसलन, कोरोना महामारी के दौरान लॉक डाउन लगने से सभी ऑटो चालक बेरोजगार हो गए

थे और उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने सभी ऑटो चालकों को दो बार 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की थी। इसके अलावा, कई तरह की लगने वाली फीस को भी माफ कर दिया।

इस दौरान ऑटो वालों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके हित में किए गए कामों के लिए धन्यवाद किया। ऑटो वालों में इस बात पर बेहद खुशी है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। विधायक संजीव झा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से ऑटो वालों को अपने परिवार का हिस्सा माना है और जब भी जरूरत पड़ी, वो हमेशा ऑटो वालों के साथ खड़े रहे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। बता दें कि बीते माह दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने प्रदेश स्तरीय ऑटो संवाद किया था। उस दौरान उन्होंने ऑटो वालों के साथ संवाद करने की घोषणा की थी। यह संवाद ''आप'' ऑटो विंग सगठन द्वारा किया जा रहा है।

केजरीवाल सरकार ने ऑटो वालों के लिए किए ये काम

-कोरोना में 2 बार 5000 रूपए, कुल 10,000 रूपए दिए

-डिम्टस की फीस 1420 रूपए सलाना से घटाकर फ्री कर दी

-सिम की फिस 584 रूपए सलाना से घटाकर फ्री कर दी

-फिटनस की फिस 600 रूपए सलाना से घटाकर फ्री कर दी

-ऑटो मीटर की रोड ट्राई खत्म की।

-ड्राइविंग लाइसेंस पर लगने वाली क्लास और फिटनेस पर लगने वाली क्लास बंद की

-परमिट फीस को 1000 से घटाकर 500 किया।

-आरसी का पता बदलनावे पर हर महीना 500 रूपए (6000 रूपए साल) पेनल्टी लगती थी, जिसे घटाकर 100 (1200 रूपय साल) कर दिया

-511 ऑटो स्टैंड बनवाये

अगले 10 दिन में खुलेगा मंगी ब्रिज, हजारों वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत

दिल्ली के मंगी पुल की दाहिनी आर्च की मरम्मत पूरी हो गई है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पुल के इस हिस्से को बड़े ट्रकों के गुजरने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ऊंचे ट्रॉला वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) आठ से 10 दिनों में पुल की इस लेन को भी शुरू कर देगा।

नई दिल्ली। मरम्मत के बाद मंगी ब्रिज की दाहिनी आर्च तैयार हो गई है, जल्द जनता को इसमें वाहन गुजारने की अनुमति मिलेगी। लालकिला के पीछे 150 साल पहले बने इस ब्रिज की दाहिनी आर्च में बड़े ट्रक गुजरने से नुकसान हुआ है। ट्रक के ट्रॉला टकरा जाने से ब्रिज का यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था।

अब काम पूरा हो चुका है। फिर से ट्रकों का ट्रॉला ना टकराए, इसे देखते हुए इस आर्च में ऊंचे ट्रॉला वाले ट्रकों के गुजरने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए ब्रिज से कुछ पहले ही हाइट बैरियर लगाए जाने का काम शुरू किया गया है जो आठ दिन में पूरा हो जाएगा।

ब्रिज की लेन शुरू होने से मिलेगी राहत

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा है कि आठ से 10 दिन में ब्रिज की इस लेन को भी शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली में ऐतिहासिक गेट और पुल बन रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के लिए चुनौती बन रहे हैं। मुख्य समस्या मंगी ब्रिज को लेकर रही है। इसके नीचे से

यातायात गुजरने से ये क्षतिग्रस्त हो रहा है।

जर्जर हालत में पहुंच चुके मंगी ब्रिज को बचाने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार कुछ न कुछ काम करता रहता है। फरवरी में इसकी दाहिनी आर्च के संरक्षण कार्य के लिए काम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ब्रिज के नीचे के भाग में मजबूती दी गई है। ब्रिज के नीचे की तरफ क्षतिग्रस्त भाग को तैयार करने में स्टील के अर्ध चंद्राकार गार्डर डाले गए हैं।

150 वर्ष पहले बना था मंगी ब्रिज

इसी तकनीक पर 2010 में इसी ब्रिज के ढह चुके आधे हिस्से को बचाया गया था। यह ब्रिज लालकिला और सलीमगढ़ किले को जोड़ता है। इतिहास लालकिला के पीछे स्थित इस ब्रिज का निर्माण 150 वर्ष पूर्व किया गया था।

इसका प्रयोग लालकिला से सलीमगढ़ किले में जाने के लिए किया जाता था। वर्तमान में इस ऐतिहासिक ब्रिज के नीचे से रिंग रोड गुजरता है। पुराना हो जाने से इस ब्रिज के ऊपर से कुछ साल से वाहनों का आवागमन बंद है।

फरीदाबाद की यातायात व्यवस्था का हाल और जनता की चुनौतियाँ

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद। दिल्ली-एनसीआर का प्रमुख शहर, पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ते यातायात जाम की समस्या का सामना कर रहा है। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या और दूसरी ओर सड़कों पर वाहन चालकों की धैर्यहीनता, शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इसी क्रम में, बंगाल शूटिंग चौक, जो कि मथुरा रोड और बाइपास रोड के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण चौक है, जाम की समस्या से जूझ रहा है।

प्रतिदिन यहां वाहन जाम में फंसे दिखाई देते हैं। यातायात प्रबंधन की कमी और लोगों में संयम की कमी ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, कई बार तो घर से कार्यालय या अन्य जगहों पर जाने में लगने वाला समय दुगना हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने ही क्षेत्र के छोटे-छोटे चौराहों पर 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ता है।

आरडब्ल्यूए और सड़क सुरक्षा स्वयंसेवक #VocalForLocalRoadSafety अभियान के तहत प्रमुखता से मांग कर रहे हैं कि मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, स्ट्रीट लाइट्स ठीक की जाएं, और विशेषकर शाम के पीक ऑफिस आवर्स में यातायात जाम से बचने के लिए बुनियादी सुरक्षा उपाय किए जाएं। इन समस्याओं के समाधान के बिना, सड़क सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना रहेगा। प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई की

अपेक्षा है ताकि भविष्य में ऐसे भारी जाम और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

इस स्थिति में लोग अक्सर प्रशासन और सरकार को कोसते हैं, लेकिन अगले ही दिन फिर से वही जाम और वही समस्याएँ उनके सामने होती हैं। इस जाम से न केवल लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि उनका कीमती समय और ऊर्जा भी बर्बाद हो रही है।

फरीदाबाद की यह स्थिति यह बताने के लिए काफी है कि अब समय आ गया है जब यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। नगर निगम की ओर से सही व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स का ठीक से काम करना, सड़कों पर छोटे-छोटे गड्ढों को भरना और ग्रीन बेल्ट की देखरेख पर ध्यान देना आवश्यक है।

शहर के निवासियों को भी चाहिए कि वे अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालें और अपने स्थानीय क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए आवाज़ उठाएँ। हर वार्ड, हर सेक्टर में नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है ताकि यातायात समस्या का समाधान हो सके।

साथ ही, वाहन चालकों को भी संयम से काम लेने की जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि यातायात नियमों का पालन न केवल उनके लिए बल्कि पूरे शहर के लिए आवश्यक है। यातायात प्रबंधन को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर नागरिक का सहयोग महत्वपूर्ण है।

सप्रिंगफील्ड कॉलोनी और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास स्थित बंगाल शूटिंग चौक, जो शेर शाह सूरी रोड पर एक प्रमुख स्थान है, हाल के दिनों में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं का केंद्र बन गया है।

इस क्षेत्र में बढ़ता यातायात और बिना किसी स्ट्रीट लाइट के काम करने वाली सड़कों ने स्थानीय निवासियों और यात्रियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हाल ही में हुए हादसों और एक दुखद मौत ने इस चौक पर सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को और भी उजागर कर दिया है।

बंगाल शूटिंग चौक पर रात के समय स्ट्रीट लाइट्स का न होना एक बड़ी समस्या है, जिससे वाहन चालकों को दृश्यता में भारी कठिनाई होती है। इसके अलावा, यातायात के दबाव में भी लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन कोई उचित यातायात प्रबंधन नहीं किया जा रहा है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सभी मुद्दों के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब समय आ गया है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।

समय आ गया है कि फरीदाबाद के नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर इस जाम की समस्या का समाधान निकालें और अपने शहर को फिर से एक सुरक्षित और सुगम यातायात वाला शहर बनाएं।

इन्दौर के गणेशोत्सव की जीवित परम्परा व संस्कृति का लोक उत्सव आज भी जारी है....

हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

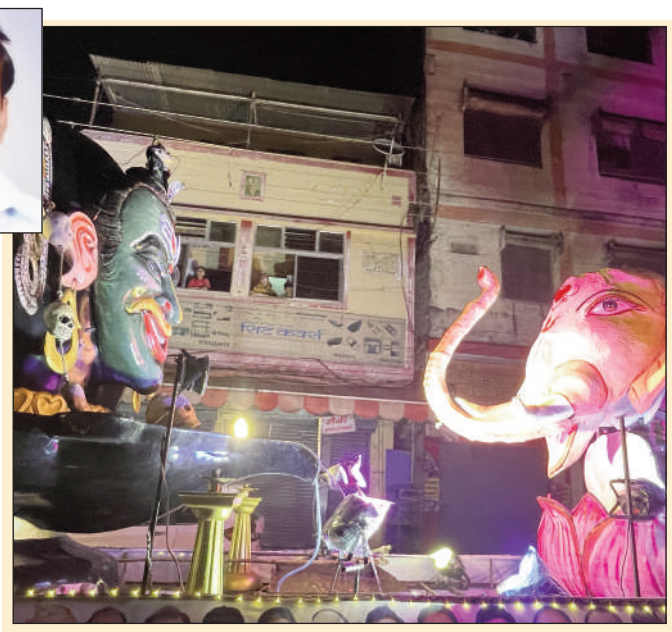

गणेश उत्सव से समाजिक दायित्व के साथ राष्ट्र भक्ति की जो ज्योत प्रज्वलित कर आजादी से पहले स्वतंत्र वीर बालगंगाधर तिलक जी ने जलाईं थी वह हम बिखरे हुए हिन्दुस्तानीयो के लिए मील का पत्थर साबित हुई ।जिससे हमारी आस्था और समृद्ध हुई विश्वास के साथ श्रध्दा और राष्ट्रीय एकता और सद्भावना भी बड़ी थी ।जो कभी भी खत्म नहीं हो सकी । तभी तो उसी विचारधारा को हमारे मध्यप्रदेश की औद्योगिक राजधानी व स्वच्छता में अव्वल शहर इन्दौर जो व्यवसायिक राजधानी भी है उसी जीवित परम्परा व लोक संस्कृति का लोक उत्सव आज भी अविरल जारी है । छोटी सी शुरुआत आज परम्परा का हिस्सा बन चुकी है । पहला गणेश विसर्जन जुलूस यहां अनन्त चतुर्दशी गणेशोत्सव चल समारोह की शुरुआत 1923 में मिल मालिक मशहूर उद्योगपति काटन आफ किंग दानवीर सर सेठ हुकुमचंद जी ने पुण्य शाली लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की इस इन्दौर नगरी में की थी। जब गणेश विसर्जन चल समारोह में लालटेन और गैस बत्ती के साथ ढोलक डमरू ढापली व विक्टोरिया बग्घियां के साथ बैलगाड़ी से झांकी निकलती थी । वह समय ऐसा था जब कपड़ा मिलों में मजदूरों के परिश्रम का डंका बजता था। वहीं पसीने की कमाई से 7 मिलो की वजह से यह इन्दौर कपड़ों का हब हुआ करता था । वह पावरलूम भी बहुत सारे थे । आज मिलों को बंद हुऐ 33 वर्ष हो चुके हैं । अब ना वह शोर गुल होता ना भोगे की आवाज ना मिलों की चिमनियों से धुआं निकालता है । कितनी बड़ी विडंबना है कि कम से कम 70 प्रतिशत मिल मजदूर संघर्ष करते रहे और अब व दुनिया छोड़ चले गए । एक लम्बी लड़ाई मजदूरों ने लड़ी पर समय के इस भंवर में उनकी आवाज अब खामोश है पर जीत उन मिल मजदूरों की हुई। सरकार अब उनको उनका हंक दे रही है। न्याय की देवी ने जो न्याय किया वह सर्वमान्य है। जो मजबूत नींव परम्परागत व संस्कृति बचाने हेतु लोगों की एकजुटता भाईचारा को बढ़ने हेतु सदियों पहले दानवीर सेठ हुकुमचंद जी ने डाली थी उसी विरासत को मिलों से जुड़े परिवारों द्वारा सहज कर आगे बढ़ाया जा रहा है। 100 वर्षों से ज्यादा पुराने इतिहास को वहीं जोश जुनून से अब भी इन्दौर ने कायम रखा हुआ है । यह बहुत ही गर्व की बात है , इस आधुनिकता के दौर में पहले जैसा रंग अब गणेश उत्सव व अनंत चतुर्दशी चल समारोह पर नहीं दिखाई देता है । जिस प्रकार उल्लास मनोरंजन के कार्यक्रम गीत संगीत कवि सम्मेलन व पर्दों पर फिल्में दिखना उसके बाद बीसीआर पर रामायण महाभारत का प्रदर्शन अब नहीं होता पर अनंत चतुर्दशी की झांकियों का सिलसिला व अखाड़ों के पहलवानों के करतबों शस्त्र कला के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है । यहीं विरासत है और इस इन्टरनेट मोबाइल के आधुनिक युग में भी जिसे अब भी, यहां हजारों बल्ब से सुसज्जित झिलमिलाती झांकियों का कारवां इन्दौर की पहचान बना हुआ है। यही यह की नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत की लोक कला का प्रदर्शन भी होता है हर एक रंग में इन्दौरी उत्सव में उल्लास ढुंढ ही लेता है । यहां पुराने समय में दो तीन दिन पहले से दूरदराज के इलाके से लोग अपनी जगह रोकने हेतु आ जातें थे । इन सौ साल से ज्यादा के सफ़र में सिर्फ करोना के दो वर्ष ही थे जब यह चल समारोह नही निकला , बाकी अविरल इस का सफर जारी है। तभी तो हमारी पहचान मिनी मुंबई के नाम से होती है महाराष्ट्र के बाद इन्दौर में ही गणेश उत्सव की अपनी एक अलग सी छवि हुआ करती है । समय के साथ उत्सव में वह उल्लास कम जरूर हुआ पर जिस प्रकार मुंबई में अंनत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन चल समारोह में वहां कोई सोता नहीं है मुंबई जागरण करती है । उसी प्रकार इन्दौर भी जागरण करता है उस रात मानों आसमान से देवता भी पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हैं शाम से पूरी रात तक दिन जैसा एहसास हर कोई करता है । आज दानदाताओं समाजसेवी व जनप्रतिनिधि की मदद से झांकियां तैयार की है और शहर के इस रतजगा में धार्मिक राष्ट्रीय देश भक्ति भाव से ओतप्रोत

30 से ज्यादा झांकियां सजाई गई है। जो शहर भ्रमण के लिए निकलेंगी ।

स्वच्छता में अव्वल शहर इन्दौर भारत का सिरमौर है उसी प्रकार वह परम्परा संस्कृति विरासत व इतिहास को सहेजने में भी सबसे आगे हैं । हमारा इन्दौर इस गणेश विसर्जन चल समारोह में पौराणिक कथाओं पर सनातन संस्कृति व धर्म पर ओर इतिहासिक प्रेरक प्रसंग बच्चों का स्वच्छ मनोरंजन के साथ विकासित भारत की बात व सरकार के सकारात्मक प्रयासों का चित्रण इन झांकियों में हो रहा है । जो शाम से मिल ऐरिये से शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा से होते हुए पूरी रात घूमतीं है सुबह मिलों में खड़ी हो जाती है वह तीन दिन देखने के लिए और रखी जाती है । एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब यह चल समारोह मशाल व लालटेन की रोशनी में निकला जाता था उस के बाद बल्ब की झिलमिलाती लाइट्स व अब एल ई डी की दूधिया रोशनी में अंनत चतुर्दशी की रात इन्दौर में अंधेरा नहीं होगा क्योंकि प्रथम पूज्य देवो के देव गजानंद गणपति जी का यह विसर्जन चल समारोह है जो प्रकाशमान बन पूरे शहर में सतरंगी छटा बिखरेगा। इसमें खास बात यह होती है इस आधुनिक युग में युवा पीढ़ी के लिए यह समारोह प्रेषित करता है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए अब जिम में लोग अपने शरीर को बनाने के लिए जाते हैं पर जो खुशबू हमारी मिट्टी के अखाड़ों में कसरत करने से आंनद की अनुभूति होती थी वह जिम में पसीना बहा कर भी नहीं होती है ।उन्हीं मिट्टी व अखाड़ों में पहलवानी करने वाले लोग भी अपने अपने अखाड़ों की शस्त्र कला करतब शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन भी इस चल समारोह में करते हैं। जिसमें बांदिश, भाला, आत्मरक्षा के लिए बनेटी, पटा गदका फरी बाना , चकरी, तलवार आदि शास्त्र कलां का प्रदर्शन करते हैं। इस में उस्ताद व खलिफाओ का स्वागत भी किया जाता है । वही इस प्रदर्शन में अब बालिकाएं भी लाठी बनेठी व तलवार व अन्य अस्त्र-शस्त्र से ढोल नगाड़ों की थप पर कलाबाजियां भी करती है । जो इस विसर्जन समारोह का मुख्य आकर्षण भी रहता है जहां शासन प्रशासन इन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित करते हैं यही हमारी आस्था की पहचान है इतनी भीड़भाड़ में बेटियां भी तलवार भाले बनेठी घुमती है जो भारत की प्राचीन कलाओं में हैं, अखाड़ों की असली पहचान पहलवानों की मेहनत से होती है तभी इस चल समारोह में यह मिट्टी वाले देशी करतब करते पहलवान उस्ताद व खलीफाओं से पुरे कार्यक्रम में चार चांद लग जाता है। आप को मालूम होगा फिल्म डान में लेखक सलीम खान इन्दौर के थे जो खुद पहलवानी करते थे तभी तो उन्होंने ने डायलॉग लिखा । जिसे अमिताभ बच्चन ने फिल्म में डायलॉग बोला था कि हम भी इन्दौर के विजय बहादुर उस्ताद के अखाड़े के पहलवान हैं। ऐसी पटकनी देंगे की चारों खाने चित कर देंगे । इन्दौर में अभी भी ऐसे पंद्रह बीस बड़े अखाड़े आज भी चल रहे हैं । यह हमारी लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर जी का पुण्य प्रताप ही है । कि यह के लोग लोक संस्कृति व संस्कार को अपनी परम्परा के रूप में अब भी कायम रखें हुऐ हैं। कितनी भी दिक्कत आये मजदूरों की अर्थव्यवस्था चाहे ठीक नहीं हो पर उनके ठोस दमदार इरादों के आगे यहां सब चीजें बहुत छोटी नज़र आती है । इन मेहनतकश मजदूरों के वंशज भी इस विसर्जन चल समारोह के सहयोग में सबसे आगे होते हैं और विघ्न विनाशक गणेश जी इस यात्रा को इस चल समारोह को निर्विघ्न संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। सर्व प्रथम इन्दौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की झांकी रहती है । अनंत चतुर्दशी की पूरी रात झिलमिलाती झांकियों का कारवां चलता रहता है, बच्चे जवान बुजुर्ग नाचते गाते मस्ती उल्लास आंनद में आगे बढ़ते रहते हैं दर्शक जो इन्दौरी होने का फर्ज अदा करते हैं वह पूरी रात इन जांबाज मजदूरों की मेहनत का रास देखते हैं इन झिलमिलाती झांकियों के रंग-बिरंगे कारवां को निहारते हैं तभी तो अंनत चतुर्दशी की पूरी रात ढोलक बैंड बाजे डी जे नगाड़ों की गुंज बच्चों के खिलौनों की सीटियां कानों गुंजती है वहीं बुजुर्गो को बचपन की याद दिलाती है बच्चों के खिलोने चकरी गुब्बारे डमरू बेचने वाले भी बच्चों को आकर्षित करतें हैं । ऐसे खेल खिलौने जो अब बड़े बड़े माल में जाने पर भी नहीं मिलते है वह यह मिलते हैं, झांकी उत्सव प्रिय शहर वासियों व मेहनतकश मजदूरों का सार्थक प्रयास ही है कि सौ साल से ज्यादा पुरानी परम्परा संस्कृति इतिहास को सहेजने हेतू वर्तमान युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी दे रही हैं । अब कुछ सालों से नगरनिगम इन्दौर व इन्दौर विकास प्राधिकरण भी इस चल समारोह में सहभागिता निभा रहे हैं। यह गर्व की बात है कि हम आज भी इन्दौर के इस गणेश विसर्जन चल समारोह में युवा वर्ग की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है नये कपोलों को अंकुरित करने हेतु इस तरह के समारोह हमेशा से प्रेरणादायक रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तभी तो पूरा शासन प्रशासन व समाजिक संस्थान धार्मिक मंदिरों के प्रबंधक सभी धर्मों के अनुयाई इस राष्ट्रीय एकता के इतिहासिक चल समारोह में जो सदियों से इन्दौर की धरोहर व आन बान शान रहा है उसमें पूरा सहयोग करते हैं । तभी तो मध्यप्रदेश के इन्दौर में यह मिल मजदूरों के मनोरंजन व शिक्षा ओर धर्म समाज व राष्ट्र भक्ति जागने का छोटा सा प्रयास आजादी के पहले शुरू हुआ जो आज परम्परा संस्कृति पर्व हमारी विरासत बन गया है इस अंनत चतुर्दशी चल समारोह की झांकियों व अखाड़ों का 100 वर्षों से ज्यादा पुराना इतिहास आज भी अविरल जारी है परम्परा संस्कृति आज इस आधुनिक युग में भी जीवित हैं । इस के लिए पूरे इन्दौर के सभी लोगों का आभार जो आप लोगो ने अपने शहर की विरासत को स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर रखा है। यह कारवां मेहनतकश मिल मजदूरों का अब हम इन्दौरीयो का लोक उत्सव व विरासत बन चुका है।

जबरी बाग नसिया इन्दौर
मध्य-प्रदेश
9826084157

चंद्र - ग्रहण, 18 सितंबर 2024, बुधवार

साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024, बुधवार को लगेगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 6:11 बजे शुरू होगा। यह ग्रहण सुबह 10:17 बजे खत्म होगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा।

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अतः इस चंद्र ग्रहण के किसी भी तरह के नियम पालन भारत में करने की आवश्यकता नहीं है। यह ग्रहण यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, आकंटिक और उत्तर, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका आदि देशों में दिखाई देगा।

ग्रहण को विज्ञान में खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष व धर्मशास्त्रों के अनुसार ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है। चंद्रग्रहण के नौ घंटे पहले ही सूतक लग जाता है।।

आंशिक चंद्र ग्रहण क्या है?

चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं: उपछाया ग्रहण , जब चंद्रमा केवल पृथ्वी के उपछाया को पार करता है;। आंशिक ग्रहण, जब चंद्रमा आंशिक रूप से पृथ्वी की छाया की प्रच्छाया (छाया का गर्भ या केंद्र) में आ जाता है और पूर्ण ग्रहण , जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया की प्रच्छाया में आ जाता है।

भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा-:

भारत में यह चंद्रग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार धार्मिक कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब होता है मान्य-:

चंद्र ग्रहण की घटना का धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व हैं। अगर चंद्र ग्रहण आपके शहर या देश में न दिखाई दे लेकिन दूसरे देशों में नजर आ रहा हो इस संबंध में भी ग्रहण से जुड़े नियम जैसे सूतक काल आदि मान्य नहीं होता है, लेकिन अगर मौसम की वजह से चंद्र ग्रहण दर्शनीय न हो तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होता है और ग्रहण से संबंधित सभी सावधानियो का पालन भी किया जाता है।।

।। सन-2024/ श्राद्ध पक्ष ।।

17 सितंबर, मंगलवार, पूर्णिमा से शुरू होकर 02 अक्टूबर, बुधवार अमावस्या को समाप्त होंगे।

पूर्णिमा, 17 सितंबर, मंगलवार (प्रातः 11-44 के बाद)

एकम, 18 सितम्बर, बुधवार (प्रातः 08-04 के बाद)

द्वितीया, 19 सितम्बर, गुरुवार,
तृतीया, 20 सितम्बर, शुक्रवार,
चतुर्थी, 21 सितम्बर, शनिवार,
पंचमी, 22 सितम्बर, रविवार,
षष्ठी, 23 सितम्बर, सोमवार,
सप्तमी, 24 सितम्बर, मंगलवार (दोपहर 12-38 तक)
अष्टमी, 24 सितम्बर, मंगलवार (दोपहर 12-38 के बाद)
नवमी, 25 सितम्बर, बुधवार (दोपहर 12-10 के बाद)
दशमी, 27 सितम्बर, शुक्रवार (दोपहर 01-20 तक)
एकादशी, 28 सितम्बर, शनिवार (दोपहर 02-49 तक)
द्वादशी, 29 सितम्बर, रविवार,
त्रयोदशी, 30 सितम्बर, सोमवार,
चतुर्दशी, 01 अक्टूबर, मंगलवार,
अमावस्या, 02 अक्टूबर, बुधवार,

कुछ पंचांग (कैलेण्डरों) में सप्तमी का श्राद्ध 23 सितम्बर, दशमी का श्राद्ध 26 सितंबर व एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को लिखा है। इसका कारण है कि इन महालय श्राद्धों का शास्त्रोक्त समय अपराह्नकाल होता है, जो कि इन दिनों में लगभग दोपहर 1-30 से 4:00 बजे तक रहेगा। यह समय देरी का होने के कारण राजस्थान क्षेत्र(उत्तर भारत) में सही नहीं बैठ पाता है। फिर भी अगर कोई इनमें कर सके तो उनके लिए ये दिन भी ठीक हैं। निम्नांकित समयानुसार करें- :

सप्तमी, 23 सितम्बर, मंगलवार (दोपहर 01-50 के बाद)

दशमी, 26 सितम्बर, गुरुवार (दोपहर 12-25 के बाद)

एकादशी, 27 सितम्बर, शुक्रवार (दोपहर 01-20 के बाद)

अनन्त चतुर्दशी, 17 सितंबर 2024 मंगलवार

अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है, इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है।

भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान (भगवान विष्णु) की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें चौदह गाँठें होती हैं।

* अनंत चतुर्दशी के दिन में श्री गणेश विसर्जन भी किया जाता है इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है।

* भारत के कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झांकियाँ निकाली जाती है।

अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा विधि अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णुजी के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है।अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है-:

* इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें।

* कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें या आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं।

* इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें, इसमें चौदह गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें।

* अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें।

"अनंत संसार महासुमद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव। अनंतरूपे विनियोजयस्व ह्यानंतसूत्राय नमो नमस्ते।।"

* पुरुष अनंत सूत्र को दांये हाथ में और महिलाएं बांये हाथ में बांधे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।

अनंत चतुर्दशी का महत्व-:

पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में चौदह लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी चौदह रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम जप/ मंत्र जप/ या श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन-धान्य, सुख-संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती है।

अनंत चतुर्दशी की कथा-:

महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि, हे मधुसूदन हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें।

इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि, अनंत भगवान कौन हैं.. ? इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैय्या पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में दो पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है न अंत का इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राज-पाट मिला।

अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त-:

* 17 सितंबर, मंगलवार सुबह 6:08 से सुबह 11:45 तक।

* अवधि 5 घंटे 39 मिनट

"इतिहास में पहली बार कोई चुनाव ईमानदारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा"

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि कल दिल्ली में जो घटना हुई उससे न केवल देश बल्कि पूरा विश्व अचंभित है I उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और आज पूरे देश के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी मामले में जमानत मिल जाने के बाद और जेल से बाहर आ जाने के बाद खुद यह कह रहा है, कि यदि आप लोगों को लगता है की मैं ईमानदार हूं तो आगामी चुनाव में मुझे वोट देना I उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत से चुनाव लड़े जाते हैं, जाति के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, भाषा के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन यह इतिहास का पहला ऐसा चुनाव होगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री खुद कह रहा है, कि इस बार ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा I सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जहां एक तरफ केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीछे अपनी सारी जांच एजेंसियों को लगा रखा है, उन्हें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद भी दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी दिल्ली की जनता पर पूरा विश्वास है और यही कारण है, कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से कह रहे हैं, कि यदि आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना ।

सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कल जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

ने इस बात का ऐलान किया है, तब से ही पूरी दिल्ली में बसों में, गली मोहल्ले में, मेट्रो में हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी जांच एजेंसियों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, उनको फसाने की जो साजिश की गई, उन्होंने अकेले केंद्र सरकार से लड़कर सच्चाई की यह जंग जीती और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा और यदि दिल्ली की जनता चाहेगी तभी मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठूंगा, उनके इस एलान ने भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के सारे षड्यंत्र को विफल कर दिया है I सौरभ भारद्वाज ने सुबह उनके साथ घटित एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया, कि जब वह सुबह बाल कटाने नाई की दुकान पर गए तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस बारे में उनके साथ बातचीत की और वह सभी लोग पूछ रहे थे, कि चुनाव कब होंगे I उन्होंने सौरभ भारद्वाज से चुनाव जल्दी कराने की बात भी कही I सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की जनता में इतनी उत्सुकता है, कि वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और वह एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं I एक अन्य व्यक्ति से फोन पर हुई बातचीत का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया, कि वह व्यक्ति उनके विधानसभा क्षेत्र में रहता है, परंतु उसकी दुकान लाजपत नगर में स्थित है I उसने बताया कि लाजपत नगर में जहां उनकी दुकान है, वहां आसपास में जो अन्य दुकानदार हैं उनमें से कुछ भाजपा के समर्थक भी हैं, वह भी इस बात को मान रहे हैं, कि यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कि एक मुख्यमंत्री खुद अपने पद से इस्तीफा दे रहा है और कह रहा है कि यदि मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना।

त्रेतायुग का एक उदाहरण देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मर्यादा की खातिर सतयुग में भगवान श्री राम ने सत्ता का त्याग किया था और 14 बरस का बनवास काटकर आए थे I भगवान राम के वनवास जाने को लेकर पूरी अयोध्या नगरी के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे और उनसे आग्रह कर रहे थे, कि आप वनवास पर ना जाएं I परंतु केवल मर्यादा की खातिर भगवान श्री राम ने सत्ता का त्याग कर वनवास काटा था I उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के भक्त हैं और भगवान श्री राम के भीतर जो आचरण थे आज उन्हीं का पालन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मर्यादा की खातिर सत्ता को त्यागने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है, कि यदि जनता को लगता है, कि मैं ईमानदार हूं और जनता जब चाहेगी तभी मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठूंगा, अन्यथा मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा।

सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड दिल्ली द्वारा स्कुल विद्यार्थियों को जीवन रक्षक प्रशिक्षण दिया जा रहा है

शम्स आगाज

नई दिल्ली। आपातकालीन प्रतिक्रिया और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र स्कूलः सरकारी (सह-शिक्षा) एसआर।एसईसी. स्कूल चरण-2, डीडीए फ्लैट्स कालका जी, नई दिल्ली - 110019 स्कूल आईडीः 1925041 दिल्ली ब्रिगेड ने गवर्नमेंट (को-एड) एसआर में एक विशेष सत्र आयोजित किया। एसईसी. स्कूल चरण -2, डीडीए फ्लैट्स कालका जी, 9 को नई दिल्ली-110019 सितंबर 2024। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को शिक्षित करना था हृदय और श्वसन संबंधी आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना। इसमें सुरक्षा दिशानिर्देश, मान्यता और चरण-दर-चरण शामिल थे- चरणबद्ध कार्रवाई, और सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) प्रदर्शन। COVID-19 के बाद से महामारी के कारण कई व्यक्ति लंबे समय तक लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, जिससे इसका खतरा बढ़ रहा है गंभीर हृदयाघात, विशेषकर युवा व्यक्तियों में।

स्कूल द्वारा समर्थित, चार शिक्षकों और 555 छात्रों ने सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया प्राचार्य एवं समिति सदस्य. सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछे और डमी पर सही सीपीआर का अभ्यास किया। उन्होंने कैजुअल्टी हैंडलिंग और शिफ्टिंग, एंडिंग भी सीखी जीवंत बातचीत के साथ.

श्री पी ड़ी वर्खिया के नेतृत्व में दक्षिण-पूर्व और दक्षिण जिलों की दिल्ली ब्रिगेड टीम। पी. डी. वेरखिया, सहायक आयुक्त, और एक सत्र का संचालन दल अधिकारी श्याम कुमार ने किया स्कूल अधिकारियों से बहुत प्रशंसा मिली। प्रशिक्षण के दौरान स्कुल प्रधानाचार्य श्री करन बेग एवं ब्रिगेड व स्कुल सम्पर्क अध्यापक श्री महिपत मीणा उपस्थित रहे दिल्ली ब्रिगेड के प्रयास महत्वपूर्ण हैं और जीवनरक्षा, और उनके ज्ञान की स्वीकार्यता उनके महत्व को रेखांकित करती है। यह संपूर्ण शिक्षा में इस जागरूकता को प्रसारित करने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है जीएनसीटी दिल्ली में संस्थान, जो वर्तमान परिदृश्य में आवश्यक है।

शालिनी सोनी, शगुन कृष्णा और कीर्ति वर्मा ने जीता प्रतिष्ठित गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया 2024 का खिताब

सुषमा रानी

नई दिल्ली। खूबसूरती और प्रतिभा से भरपूर कार्यक्रम में, शालिनी सोनी , शगुन कृष्णा और कीर्ति वर्मा को गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया 2024 के विजेताओं के रूप में ताज पहनाया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन शनिवार को नई दिल्ली के द सूर्या होटल में आयोजित किया गया। भारत की नंबर 1 हिंदी महिला पत्रिका गृहलक्ष्मी द्वारा आयोजित इस ब्यूटी पेजेंट में आधुनिक भारतीय महिलाओं की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का उत्सव मनाया गया। मार्गरेट एपी, काजल विशाल शेवाले, शिल्पा मानवानी, रेनू जिंदल, वत्सला जोसेफ, राधिका भूषण को रनर अप्स के रूप में ताज पहनाया गया।

गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया 2024 प्रतियोगिता में देशभर की विवाहित महिलाओं के सपनों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस इवेंट में तीन श्रेणियों – एलीट, गोल्ड और सिल्वर – में फाइनलिस्ट शामिल थीं, जो प्रत्येक प्रतियोगी को अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ अलग बनाती हैं।

इस इवेंट को इन्फ्लुएंसर सोनम छाबड़ा ने होस्ट किया और अपनी आकर्षक उपस्थिति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विजेताओं को एक प्रतिष्ठित जूरी पैनल ने ताज पहनाया, जिसमें शहनाज हुसैन, बॉलीवुड अभिनेत्री सयाली भगत, इंडियन फैशन डिज़ाइनर ललित डालमिया, टीवी अभिनेत्री कविता घई, यूट्यूबर प्रेरणा मल्हान, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर डॉ. जय मदान, दीवा पेजेंट्स के निदेशक कार्ल मास्करेन्हास, एंटरप्रेन्योर और ज्वेलरी डिज़ाइनर मिताली हांडा और न्यूट्रिशनिस्ट और ऑथर कविता देवगन शामिल थे। इन सेलिब्रिटी जजों की उपस्थिति ने इस पहले से ही सितारों से सजी रात को और भी ग्लैमर से भर दिया।

विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों से बनी जूरी ने विजेताओं को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विशेषज्ञता और बारीकी से किए गए अवलोकनों ने यह सुनिश्चित किया कि केवल सबसे

योग्य प्रतियोगी ताज पहनें।

गृहलक्ष्मी मैगज़ीन की एडिटर-इन-चीफ श्रीमती वंदना वर्मा ने कहा, ₹गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया पेजेंट सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है, जो विवाहित महिलाओं की आकांक्षाओं और उपलब्धियों का जश्न मनाती है, जो अपने परिवारों और समुदायों के लिए शक्ति के स्तंभ हैं। यह आयोजन ब्यूटी, ग्रेस और सबस्टेंस का मिश्रण है, जो समाज में महिलाओं की बहुमुखी भूमिकाओं को समर्थन और मान्यता देने के लिए गृहलक्ष्मी पत्रिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड और बॉलीवुड अभिनेत्री सयाली भगत ने कहा, ₹इस उत्सव का हिस्सा बनकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। पेजेंट्स केवल सुंदरता के बारे में नहीं होते, ये महिलाओं की दृढ़ता और ताकत को प्रदर्शित करते हैं। इन महिलाओं की जुनून, आत्मविश्वास और सितारों तक पहुंचने की आकांक्षा ने मुझे गहराई से प्रेरित किया है।"

दीवा पेजेंट्स के फाउंडर और डायरेक्टर्स अंजना और कार्ल मास्करेन्हास, जो गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया के आधिकारिक ग्रूमिंग पार्टनर थे, ने कहा, ₹खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह भीतर से निकलती है। दीवा पेजेंट्स में, हम हर फाइनलिस्ट को जीवन में जीतने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, केवल ताज जीतने पर नहीं। इन अद्भुत महिलाओं के साथ अपना अनुभव साझा करना और उन्हें 'डेयर, ड्रीम, डैज़ल' के लिए प्रेरित करना हमारे लिए सम्मान की बात थी।"

शराब घोटाले में संलिप्तता या जेल जाने पर इस्तीफा क्यों नही दिया : देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले के बाद दिल्ली की जनता राहत महसूस कर रही है क्योंकि जिसे जनता ने ईमानदार समझकर सत्ता सौंपी थी वो भ्रष्टाचारियों के सरगना निकले। केजरीवाल के इस्तीफे के निर्णय से जनता कह रही है कि दिल्ली को भ्रष्टाचारी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज के बयान कि नैतिकता और मर्यादा के लिए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है और केजरीवाल को पद का लालच नही है। इस पर यादव ने कहा कि अगर केजरीवाल मर्यादित पुरुष है, नैतिक रुप से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। मैं कहना चाहता हूँ अगर पद का लालच नही थाए तब शराब घोटाले में नाम आने के तुरंत बाद या जेल जाने पर ही इस्तीफा क्यों नही दिया।

यादव ने कहा कि जब केजरीवाल को पद का लालच नही है। तो उनका बयान कि जनता की अदालत में जाऐंगे और जनता के फैसले के बाद ही मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे, अगर उन्हें जनता की सेवा करनी ही है तो बिना मुख्यमंत्री रहते हुए भी कर सकते है, जिस तरह से आई.आर.एस. अधिकारी से इस्तीफा देकर समाज सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अपना जवाब लोकसभा चुनाव में दे चुकी है और दिल्ली की तबाही के बाद जनता खुद केजरीवाल का इंतजार कर रही है कि उन्होंने पिछले 3 विधानसभा और 2 दिल्ली नगर निगम चुनावों

जो वादे किए थे उनमें कितने पूरे किए है। जनता के हक के पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के बाद जनता केजरीवाल से हिसाब मांगने का इंतजार कर रही है।

उन्होने बताया कि केजरीवाल की नैतिकता उस समय कहां थी जब दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के कारण जलभराव, करंट, नालों में डूबने से 43 लोगों की जान चली गई। उन्होंने क्यों नहीं जेल से ही सबको न्याय देने के आदेश जारी किए, परंतु आज भी इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नही। एक दूसरे पर आरोप की राजनीति का खेल चल रहा है। दिल्ली की जनता कोविड महामारी में मचे मौत के तांडव को भूले नही है जब केजरीवाल दिल्ली की जनता महामारी का प्रकोप झेलने के लिए छोड़कर खुद छिप कर बैठ गए थे। यादव ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सफाई, सड़क, नाली, नाले, परिवहन, पर्यावरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, पिछले 5 वर्षों से आप के विधायक क्षेत्र से गायब रहे। केजरीवाल सहित इनके मंत्री, संत्री, विधायक, पार्षद यहां तक कि छोटे नेता तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है और 20 मंत्री और विधायक जेल जा चुके है।

उन्होंने बताया कि हर चुनाव में उनकी नौंटकी कि आपका बेटा हूँ एक बार मौका दो, अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल भ्रष्ट है और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने से पहले केजरीवाल दिल्ली की जनता को पिछले चुनाव में दी गई 10 गारंटियों का हिसाब दें। केजरीवाल सरकार की नाकामियों के कारण 10 वर्षों में दिल्ली विकास और प्रगति के मामले में 50 साल पीछे हो गई है। केजरीवाल ने दिल्ली को विश्व की नम्बर वन भ्रष्टाचारी राजधानी बना दिया है, किसी भी राज्य के लिए इससे बड़ा अपमान नही हो सकता और केजरीवाल कहते है कि जनता के बीच जाकर उनसे न्याय मांगेंगे। जबकि कुछ दिन पहले इनके आपका विधायक आपके द्वार में कहा गया कि 5 वर्षों में किए कामों का लेखा जोखा देंगें।

यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा हर सप्ताह प्रचार का एजेंडा बदलना का मतलब साफ हैए केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि जनता में आम आदमी पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है ।का फ़ैसला लिया है।

मर्कज़ी अंजुमन ईद मिलाद-उल-नबी द्वारा जुलूस का आयोजन किया गया

सुषमा रानी

नई दिल्ली: मर्कज़ी अंजुमन ईद मिलाद-उल-नबी ने इस वर्ष भी एक जलसा और जुलूस का आयोजन किया। जुलूस से पहले मेन रोड, बाड़ा हिंदू राव में एक जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक नेताओं ने भाग लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की. अंजुमन अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अहमद, संयोजक हाजी मोहम्मद शमीम कुरेशी, हाजी मेहरबान कुरेशी व अन्य सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया.

जलसा की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से हुई। बाद में मौलाना आज़ाद आलम ने पैगंबर इस्लाम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हम ब्रह्मांड के उस महान व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने मानवता का सिर ऊंचा किया और समानता, न्याय, की वकालत की। सहनशीलता, उपासना और तपस्या, उदारता, वीरता की मिसाल कायम की जो दुनिया में कोई

नहीं कर पाएगा। जहाँ आपने पुरुषों की महानता का बयां किया, वहीं माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग रखकर महिलाओं का सम्मान भी किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपोरा ने कहा कि जब भी ईश्वर किसी पैगंबर को भेजता है, तो वह उसे लोगों की भलाई और मानवता के उत्थान के लिए भेजता है। पूर्व सांसद जे प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि आज बहुत गौरवशाली दिन है, आज हमें भाईचारे, राष्ट्रीय एकता के संदेश को और मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

मंत्री इमरान हुसैन ने कहा इस्लाम शांति और मानवता के अस्तित्व का धर्म है। पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने कहा कि आज जब कुछ लोग देश के शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने की साजिश रच रहे हैं, तो आइए हम एकजुट होकर पूरे देश में एक संदेश दें। नारायण भिक्खु राम जैन ने कहा कि मेरा जन्म इसी पुरानी दिल्ली में हुआ है और यहां सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते आए हैं, आज हमें इस प्रेम को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। पूर्व पार्षद इमरान इस्माइल , मुहम्मद फ़हीम ने भी तकरीर की। गौरतलब है कि नारायण भिक्को राम, फैसल हसन और बिलाल की ओर से 46 वर्षों तक लगातार जुलूस निकालने पर सदस्यों को एक ट्रॉफी भी प्रदान की गई। इस बीच, समिति के सदस्यों में नईम अहमद पीरजी, जान आलम, वरिष्ठ पत्रकार फरजान कुरेशी, मुहम्मद असलम, मुहम्मद सुभान, मुहम्मद समी, मुहम्मद रिजवान, मुहम्मद सेहान, मुहम्मद शब्बर और पूर्व मेयर जय प्रकाश, फैसल हसन, बिलाल, जिया आशिकीन , मुस्तफा कुरेशी, माहिर रजा, मजाहिर रजा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

#VocalForLocalRoadSafety फरीदाबाद को सुरक्षित बनाने का संकल्प

सम्मानित प्रशासन एवं प्रिय नागरिकों,

हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों की मांग करें और समाज में हो रहे अन्याय के प्रति जिम्मेदारियों को स्पष्ट करें। केवल दोषारोपण से कुछ हल नहीं निकलता, हमें अपने समाज में हो रही लापरवाहियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से आवाज उठानी होगी। हाल ही में जो हादसा हुआ, जिसमें दो बैंक कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, वह हमारे लिए एक चेतावनी है। यह घटना देशभर में चर्चा का विषय बन चुकी है और अब समय है कि हम फरीदाबाद को और अधिक सुरक्षित बनाएं।

हमारे पास अब समय नहीं है वादों का, हमें उन पर ज़मीन पर कार्यवाही चाहिए। फरीदाबाद में हम सड़क सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर ठोस कदमों की मांग कर रहे हैं। अब और जानें खोने का कोई स्थान नहीं है। हमें प्रशासन से अपेक्षा है कि वे इस मामले में त्वरित और जिम्मेदार कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों।

फरीदाबाद, जो दिल्ली-एनसीआर का एक अभिन्न हिस्सा होते हुए भी, अभी तक वह मुकाम नहीं हासिल कर पाया है जो इसके पड़ोसी शहरों ने कर लिया है। ऐसे में हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हमने अपने शहर के प्रति क्या रवैया रखा है। छोटे-छोटे गड्ढों को नजरअंदाज न करें, बल्कि उन पर ध्यान दें। सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, हम सभी की है।

आज का समय है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें। चालन से डरने की बजाय, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर सही कदम उठाएं। यदि कहीं कोई लापरवाही हो रही है, तो आवाज उठाएं। पर यह आवाज गुस्से और झगड़े की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजबूती और दृढ़ता से प्रशासन के सामने अपनी बात रखें, ताकि फिर से किसी नागरिक की जान लापरवाही के कारण न जाए।

आइए, हम सब मिलकर #VocalForLocalRoadSafety की दिशा में ठोस कदम उठाएं और अपने शहर को सुरक्षित बनाएं।

छोटे बच्चों को लाईफ सेविंग प्रशिक्षण देना शुरू किया

पीडी वर्खिया

परिवहन विशेष दिल्ली: लाइफ सेवर फाउंडेशन रजि0 दिल्ली ने लाईफ सेविंग प्रशिक्षण छोटे बच्चों को देना शुरू किया जिससे छोटे बच्चे भी छोटी मोटी चोट लगने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। साथ ही उनको यह भी समझ हो उनको किस समय क्या करना है। इस दौरान बच्चों को सीपीआर की भी जानकारी दी गई साथ ही रोगी को दुर्घटना के स्थान से सुरक्षित स्थान पर या नजदीकी हस्पताल व डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे ले जा सकते हैं।

प्रशिक्षण में 06 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण को बच्चों ने बहोत पसंद भी किया और बहोत ही उत्साह के साथ सीखा भी।

सीपीआर के प्रशिक्षित ट्रेनर श्री पी ड़ी वर्खिया जोकि लाइफ सेवर फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं साथ ही श्रीमती मोनिका जोकि फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। उनसे इस विषय पर जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लाइफ सेवर फाउंडेशन आज के परिवेश में जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं उनमें से बहोत से लोगों को समय पर फ़र्स्ट ऐड या सीपीआर नही मिल पाती जिस कारण बहोत से लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं।

ऐसे में लाईफ सेवर फाउंडेशन देश के नागरिकों के लिये फ़र्स्ट ऐड की ट्रेनिग शुरू कर रही है जिंसमे प्रमुख इमरजेंसी रिस्पांस या सीपीआर है।

यह प्रशिक्षण एक दिवसीय व तीन दिवसीय होगा हमारी प्राथमिकता होगी स्कुल कॉलेज आर डब्ल्यु ए आदि जहां से भी रिक्वेस्ट आयेगी वहां जाकर उपरोक्त प्रशिक्षण देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। उन्होंने आम जनता से सम्पर्क करने के लिये फाउंडेशन की मेल व मोबाईल नम्बर भी जारी किया।

हरियाणा की चार सीटों पर अपनों ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन, बगावती तेवर से बढ़ी सियासी हलचल

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कई नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर पार्टी आलाकमान को चुनौती दी है। पटौदी और सोहना सीट से तीन कांग्रेस नेता निर्दलीय मैदान में आ गए हैं। गुड़गांव और बादशाहपुर सीट पर भी सबकुछ ठीक नहीं है। इन दोनों सीटों पर भी अंदरखाते द्वंद्व चल रहा है।

गुरुग्राम। भाजपा के बाद कांग्रेस में भी बगावत कर कई नेताओं ने निर्दलीय नामांकन कर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। अगर पार्टी हाईकमान की ओर से इन्हें मनाकर नामांकन वापस नहीं कराया जा सका तो ये नेता कांग्रेस प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। पटौदी और सोहना सीट से तीन कांग्रेस नेता निर्दलीय मैदान में आए हैं।

कांग्रेस नेताओं ने दिखाए बगावती तेवर

वहीं गुड़गांव और बादशाहपुर सीट पर भी सबकुछ ठीक नहीं है। इन दोनों सीटों पर भी अंदरखाते द्वंद्व चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बादशाहपुर और गुड़गांव सीट पर आठ सितंबर को ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। भाजपा में बगावत का दौर शुरू होने पर कांग्रेस ने पटौदी और सोहना सीट से प्रत्याशियों की घोषणा को अंतिम दिन तक होल्ड पर रखा। 12 सितंबर की रात पटौदी से पर्ल चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया।

पर्ल पूर्व विधायक स्व. भूपेंद्र चौधरी की बेटी हैं। वर्ष 2005 में कांग्रेस टिकट पर भूपेंद्र चौधरी ने इस सीट से जीते थे। उसके बाद 2009, 2014 तथा 2019 में कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाई। सुधीर चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा था। 2014 में ये तीसरे और 2019 में चौथे स्थान पर रहे।

दो बार हारे नेताओं को नहीं मिलेगा टिकट

पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हें 18984 वोट मिले थे। इस बार भी इन्होंने टिकट की दावेदारी कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने दो बार हारे और जमानत जब्त करा चुके नेताओं को टिकट नहीं देने की घोषणा की थी। इसलिए टिकट कटने पर ये पार्टी से बगावत पर उतर आए और निर्दलीय नामांकन भर दिया। दूसरी ओर सोहना सीट से भी दो वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से बगावत की।

इस सीट से रोहतास खटाना को कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन पार्टी में शामिल कराकर टिकट दिया था। यहां से 54 नेता दावेदारी कर रहे थे। टिकट की दौड़ में शामिल रहे डॉ. शमसुद्दीन और अरिदमन सिंह बिल्लू यहां से निर्दलीय मैदान में हैं। डॉ. शमसुद्दीन ने कांग्रेस के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ा था। 10735 वोट पाकर ये चौथे स्थान पर रहे थे।

कांग्रेस के वोट बैंक में लग सकती है सेंध

अरिदमन सिंह ने क्षेत्रीय पार्टियों से 1991 और 1996 में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। ये दो महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। राजपूत समाज से आने वाले अरिदमन सिंह की समाज पर अच्छी पकड़ है। फिलहाल निर्दलीय उतरे सभी नेताओं को हाईकमान की ओर से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। निर्दलीय उतरे नेताओं के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है।

वाट्सएप ग्रुपों में भड़ास निकाल रहे नेता

गुड़गांव और बादशाहपुर सीट पर भी सबकुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा पटौदी और सोहना सीट से बगावत खुलकर सामने आई है। गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से नेताओं में अंदरखाते द्वंद्व चल रहा है। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन नेताओं के समर्थक वाट्सएप ग्रुपों में भड़ास निकाल रहे हैं।

गुड़गांव सीट से 32 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी कर रखी थी। यहां से पार्टी ने जातीय समीकरण को साधकर पिछले महीने कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले मोहित ग्रोवर को मैदान में उतारा है। बादशाहपुर से वर्धन यादव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से भी 17 नेताओं ने दावेदारी की थी। दोनों ही सीटों पर पार्टी के जिले के कई वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं।

सुधीर चौधरी ने नामांकन वापस लेने के दिए संकेत

निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने शनिवार को नामांकन वापस लेने के संकेत दिए हैं। इससे पहले शनिवार दोपहर उन्होंने नई अनाजमंडी जटौली में समर्थकों के साथ पंचायत की।

पंचायत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सुधीर चौधरी को फोन कर मनाने की कोशिश की। इस पर पंचायत में निर्णय लिया गया कि एक कमेटी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान से मुलाकात करेगी और रविवार तक निर्णय ले सकती है।

आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री ने गुरुग्राम में दे दिया बड़ा बयान

वरिष्ठ भाजपा नेता व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आरक्षण को बयान दिया है। उन्होंने यह बयान गुरुग्राम में जिला भाजपा कार्यालय गुरुकमल में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के दौरान दिया है। बता दें कि हरियाणा में पांच अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं।

गुरुग्राम। वरिष्ठ भाजपा नेता व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि जब तक भाजपा है तब तक कोई आरक्षण को छू भी नहीं सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। उनका असली एजेंडा आरक्षण को समाप्त करना है।

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को डराते हुए कहा कि भाजपा अगर तीसरी बार आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस ही आरक्षण को खत्म करना चाहती है।

हरियाणा में भाजपा की सरकार आना जरूरी

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय गुरुकमल में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास और तरक्की के लिए तीसरी बार भाजपा सरकार जरूरी है। पांच अक्टूबर को चुनाव होना है। अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में कई स्तर पर दिन-रात प्रयास करना होगा।

कांग्रेस लोगों को ठगने का चलाती है भ्रम

चुनाव के समय लोगों को ठगने के लिए कांग्रेस भ्रम, झूठ और अफवाहों का नेरेटिव चलाती है। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करना तथा मोदी और नायब सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की ही जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार ने 10 वर्षों में देश और प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदला है।

10 वर्षों में हुए परिवर्तन को लोग भी महसूस कर रहे हैं। हर बूथ पर कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर हरेक व्यक्ति से मिलें और उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। भाजपा जिलाध्यक्ष कमल यादव ने अर्जुनराम मेघवाल को भरोसा दिलाया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलेगा।

बैठक में प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, जिला प्रभारी संदीप जोशी, जिला महामंत्री रामबीर भाटी, एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व उद्योगपति बोधराज सीकरी, महेश चौहान, जिला मीडिया प्रमुख पवन यादव, सह मीडिया प्रभारी राकेश राणा आदि मौजूद रहे।

गाजियाबाद उपचुनाव में खेला कर सकती है कांग्रेस-सपा, BJP की बढ़ रही टेंशन

गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर जल्द ही चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है। कांग्रेस और सपा में टिकट के दावेदारों की लाइन लगी है। संगठन स्तर पर अभी जिला और महानगर कांग्रेस की कमेटी का गठन नहीं हो सका है। जबकि सपा से गठबंधन में कांग्रेस इस सीट पर दावेदारी कर रही है।

गाजियाबाद। भाजपा से वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट से विधायक बने अतुल गर्ग को पार्टी ने लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें वह बड़े अंतर से जीतकर संसद पहुंच गए। अब गाजियाबाद विधानसभा सीट रिक्त है और यहां उपचुनाव होना है।

विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार है, लेकिन बात संगठन के नाम पर अभी तक जिला और महानगर कमेटी का गठन नहीं हो सका है।

उधर, गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के जिला और महानगर के अलावा पार्टी के अधिकांश प्रकोष्ठ की कमेटी गठित होने के साथ ही बूथ व सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त करके इन पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए।

उपचुनाव से पहले विपक्षी दलों को झटका देने की तैयारी में BJP, नई घोषणा से बढ़ेगी सियासी हलचल

जल्द जारी हो सकती है चुनावी अधिसूचना

विधानसभा उपचुनाव को लेकर जल्द ही चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है। कांग्रेस में प्रत्याशी बनने के लिए एक लंबी कतार है। पार्टी द्वारा बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया को जिला प्रभारी के रूप में गाजियाबाद भेजा गया, जिनके समक्ष 15 से अधिक ने विधानसभा उपचुनाव के लिए दावेदारी करते हुए बॉयोडाटा सौंपा।

संगठन स्तर पर अभी जिला और महानगर कांग्रेस की कमेटी का गठन नहीं हो सका है। जबकि सपा से गठबंधन में कांग्रेस इस सीट पर दावेदारी कर रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह इस सीट पर कभी सपा ने विधानसभा चुनाव नहीं जीता है।

सपा ने अधिकांश प्रकोष्ठ की कमेटियां की गठित

2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने रालोद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। सपा की जिला और महानगर कमेटी गठित होने के साथ ही पार्टी के अधिकांश प्रकोष्ठ की कमेटियां बन चुकी हैं।

वहीं, उपचुनाव से पूर्व बूथ और सेक्टर अध्यक्षों की घोषणा के साथ ही उनकी निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। सपा संगठन मजबूती के लिए जहां कालेज और कॉलोनी व सोसायटी में सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं, कांग्रेस में अभी उपचुनाव को लेकर दावेदारी जैसी उर्जा दिखाई नहीं दे रही है।

भाजपा को फिर लगा तगड़ा झटका, अब मनीता गर्ग ने बढ़ाई टेंशन; कांग्रेस क्यों है BJP से आगे?

Haryana Election 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। नगर पालिका की अध्यक्ष मनीता गर्ग ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस प्रत्याशी रोहताष खटाना का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। पढ़िए आखिर कांग्रेस बीजेपी से कैसे आगे है?

गुरुग्राम। Haryana Election 2024 हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब नगर पालिका की अध्यक्ष मनीता गर्ग ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि, बागियों को मनाने में बीजेपी से आगे कांग्रेस रही है।

भाजपा में मची है भगदड़

सोहना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में उतरीं तावड़ नगर पालिका की अध्यक्ष मनीता गर्ग ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रोहताष खटाना के समर्थन में अपना नामांकन भी वापस ले लिया। मनीता गर्ग भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं।

बागियों को मनाने में भाजपा से आगे रही कांग्रेस

सोहना विधानसभा क्षेत्र में अपने बागी अरिदमन सिंह बिल्लू एवं डॉ. शमसुद्दीन के साथ ही पटौदी क्षेत्र में बागी सुधीर चौधरी को मनाने में कांग्रेस कामयाब रही। तीनों ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया।

वहीं, दूसरी तरफ बागियों को मनाने में भाजपा पूरी तरह विफल साबित हुई। जिला परिषद के चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान एवं सुभाष बंसल जहां सोहना से निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं तो वहीं मनीता गर्ग ने पार्टी को अलविदा कह दिया। गुड़गांव में नवीन गोयल को भी मनाने में भाजपा विफल रही।

उधर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को सोनीपत पहुंच कर कविता जैन के पति राजीव जैन को मना लिया। सीएम ने 15 मिनट तक बंद कमरे में राजीव जैन के साथ मुलाकात की। इसके बाद राजीव जैन अपने कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने नामांकन वापस लेने की भी बात कही है।

दोबारा कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, 2015 में ये वादा करने वाले केजरीवाल अपनी बात से क्यों मुकरे?

नीरज कुमार दुबे

एक समय सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आंदोलन करते रहे अरविंद केजरीवाल राजनेता बनने के बाद भी अपने अंदर के आंदोलनकारी को जिंदा रखे हुए हैं इसलिए हर बात पर उनका उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से झगड़ा होता रहता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए जनता से ''ईमानदारी का प्रमाणपत्र'' मिलने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने का संकल्प लिया है। यदि उनके इस संकल्प को राजनीतिक आधार पर देखें तो इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन अगर केजरीवाल के इस संकल्प को नैतिकता के आधार पर देखें तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यही है कि जब सरकार का कार्यकाल छह महीने से भी कम का बचा है तब इस्तीफा देने का ऐलान क्यों किया गया? सवाल यह है कि जेल से छह महीने तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड केजरीवाल ने क्यों बनाया? केजरीवाल ने इस साल मार्च में तभी इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा था? केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली सरकार को अदालत की फटकारों के बाद ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? केजरीवाल को यदि अपनी ईमानदारी पर जनता की मुहर ही लगवानी थी तो उन्होंने ईडी की ओर से पूछताछ के लिए भेजे गये पहले समन में ही अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराई थी? क्यों केजरीवाल ने ईडी के आठ समनों की अनदेखी की थी? संविधान और कानून को सर्वोपरि मानने की बात कहने वाले केजरीवाल ने क्यों ईडी के बुलावे को गंभीरता से नहीं लिया था? लोकसभा चुनावों के दौरान जब जनता ने आम आदमी पार्टी के 'जेल का जवाब वोट से' अभियान को खारिज कर दिया तभी केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? केजरीवाल ने इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया था जब गर्मियों के दौरान दिल्ली की जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही थी? केजरीवाल ने इस्तीफा तब क्यों नहीं दिया था जब दिल्ली में बारिश का पानी भर जाने से छात्रों की कोचिंग सेंटर में डूब कर या सड़क पर चलते हुए करंट लग कर मौत हो रही थी? सवाल यह भी उठता है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही उनसे इस्तीफा लेने वाले केजरीवाल ने वही नीति अपने लिये क्यों नहीं अपनाई थी?

सवाल यह भी है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन चलाने वाले और जन लोकपाल के लिए आंदोलन चलाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में जन लोकपाल क्यों नहीं बनाया? सवाल यह भी है कि राजनीति में आने से पहले शराब के ठेकों का विरोध करने वाले केजरीवाल ने दिल्ली में शराब के ठेकों की संख्या बढ़ाने और दारू की एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री देने का अभियान क्यों चलाया? सवाल यह भी है कि राजनीति में आने से पहले दूसरे नेताओं को भ्रष्टाचारी बता कर उनके इस्तीफे की मांग करने वाले केजरीवाल ने राजनीति में आने के बाद एक एक कर सारे घोटालेबाज नेताओं से हाथ क्यों मिलाया? सवाल यह भी है कि राजनीति बदलने का सपना दिखाकर दिल्ली की जनता का वोट लेने वाले केजरीवाल ने बदलाव को खुद पर ही क्यों आजमाया? सवाल यह भी है कि सरकारी घर नहीं लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपने लिये सरकारी खर्चे पर शीश महल क्यों बनवाया? सवाल यह भी है कि सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा में दिल्ली और पंजाब पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में क्यों लगवाया? सवाल यह भी है कि सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपने लिये आलीशान गाड़ियों का काफिला क्यों तैयार करवाया? सवाल यह भी है कि अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते ही इस्तीफा ले लूंगा का वादा करने वाले केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और अमानतुल्ला खान जैसे विधायकों पर तमाम आरोपों के बावजूद उनका इस्तीफा क्यों नहीं करवाया?

सवाल यह भी है कि 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की जनता से 'फिर कभी इस्तीफा देकर भागूंगा नहीं' कहने वाले केजरीवाल ने अपना वादा क्यों तोड़ा? हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली में 49 दिन की पहली सरकार चलाने के बाद जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तब उन्होंने सोचा था कि 2014 के लोकसभा चुनावों में जनता उनको समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना देगी। इसीलिए वह वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुँच गये थे लेकिन जनता ने वाराणसी और देश के अन्य भागों में उनकी उम्मीदों पर बुरी तरह पानी फेर दिया था। इसके बाद दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले को अपनी गलती मानते हुए जनता से माफी मांगी थी और आगे से ऐसा नहीं करने को कहा था। लेकिन केजरीवाल ने फिर से ऐसा कर दिया है तो सवाल उठता है कि जनता उनकी बात पर भरोसा क्यों करे?

वैसे देखा जाये तो केजरीवाल ने भरोसा सिर्फ जनता का तोड़ा हो ऐसा नहीं है। उन्होंने हर चुनाव में यमुना मैय्या से वादा किया कि अगले चुनावों से पहले नदी को पूरी तरह साफ करा दूंगा। लेकिन वादा तोड़ दिया। केजरीवाल ने वादा किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनवा दो मैं दिल्ली में हर साल सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को खत्म करवा दूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गयी मगर दिल्ली में प्रदूषण कम या खत्म होने की बजाय बढ़ गया। केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध का फैसला किया मगर केजरीवाल के जेल से छूटते ही पटाखे चलाकर अपनी ही सरकार के फैसले का मखौल उड़ाया। केजरीवाल दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्रांति का ढोल हर जगह पीटते हैं लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 11 साल के शासन में कितने नये स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनवाये हैं? केजरीवाल खुद को राष्ट्रभक्त बताते हैं इसलिए उन्हें बताना चाहिए कि उनकी पार्टी पर खालिस्तान समर्थकों से चंदा लेने के जो आरोप हैं उसकी सच्चाई क्या है? केजरीवाल कहते हैं कि उनकी आवाज को दबाया जाता है लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के अब तक के शासन में दिल्ली विधानसभा में विपक्षी विधायकों को निलंबित करने का रिकॉर्ड क्यों बनाया गया?

बहरहाल, एक समय सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आंदोलन करते रहे केजरीवाल राजनेता बनने के बाद भी अपने अंदर के आंदोलनकारी को जिंदा रखे हुए हैं इसलिए हर बात पर उनका उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से झगड़ा होता रहता है। जबकि दिल्ली में पूर्व की सरकारों के दौरान मुख्यमंत्रियों का कभी भी उपराज्यपाल या केंद्र से इस तरह का टकराव नहीं रहा। इस तरह का टकराव दिल्ली में तब भी नहीं दिखता था जब राज्य और केंद्र में अलग पार्टियों की सरकारें थीं। मगर केजरीवाल पहले नजीब जंग से लड़ते रहे, फिर वह अनिल बैजल से भिड़े और अब उनका संग्राम उपराज्यपाल वीके सक्सेना से होता रहता है। इस उदाहरण से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि खामी उपराज्यपाल के स्तर पर है या मुख्यमंत्री के स्तर पर। खैर... केजरीवाल प्रकरण से एक बात तो स्पष्ट है कि एक समय पर नेता और एक्टिविस्ट की भूमिका निभाना दोनों भूमिकाओं के साथ अन्याय करने जैसा है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

भारत में आने वाली है चीनी कारों की बाढ़? क्या है ड्रैगन का नया प्लान

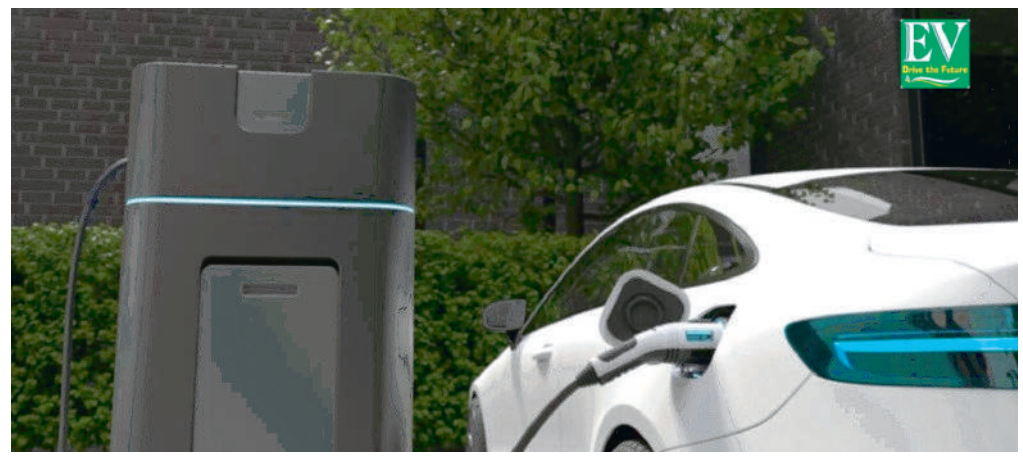

परिवहन विशेष न्यूज

आने वाले दिनों में भारत में सस्ती चीनी इलेक्ट्रिक कारों की बाढ़ आ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों में चीनी उत्पादों के खिलाफ व्यापारिक बाधाएं देखने को मिल रही हैं।

जीटीआरआई की रिपोर्ट कहती है कि ईवी की 80 फीसदी लागत चीन द्वारा उत्पादित बैटरियों और कलपुर्जों से आती है। ऐसे में भारत ईवी विनिर्माण क्षेत्र में चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हो सकता है।

इस साल मई में अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया। यूरोपीय संघ ने इसके पीछे की वजह भी बताई थी। दूसरी ओर, कनाडा ने टैरिफ में 100 प्रतिशत की वृद्धि की और स्टील और एल्युमीनियम के चीनी आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया।

चीन की SAIC मोटर यानी एमजी ब्रांड के मालिक और भारत के जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बीच साझेदारी की गई है, जिनका टारगेट 2030 तक दस लाख से अधिक नए व्हीकल्स बेचने का है।

जीटीआरआई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए सॉलिड-स्टेट बैटरी और हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करे।

एक मजबूत बैटरी रीसाइक्लिंग और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए क्लीन एनर्जी सोर्स का समर्थन करने की अपील की गई है। ईवी प्रोडक्शन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए भी जीटीआरआई ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पोजल से संबंधित पर्यावरणीय नियमों को कड़ाई से मानने की सलाह भी दी है।

बंगाल में ई-रिक्शा पंजीकरण को सरल बनाया जाएगा, अवैध वाहनों पर लगाई जाएगी रोक

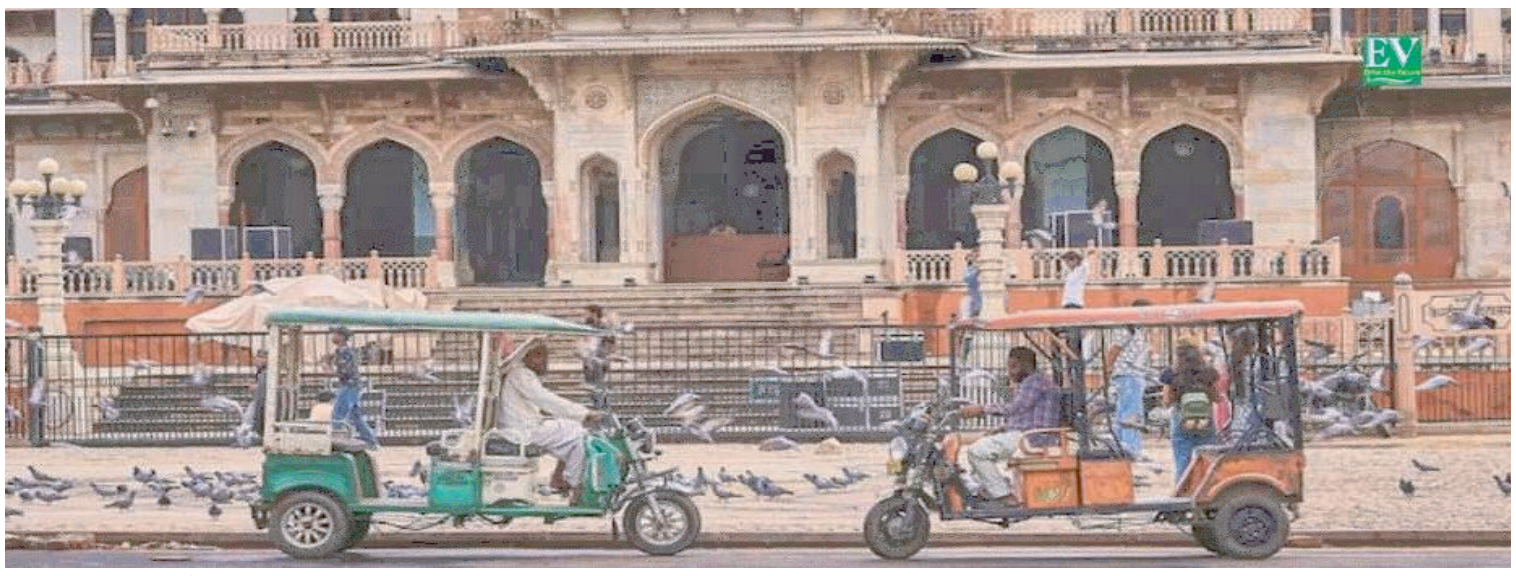

परिवहन विशेष न्यूज

पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने तथा अपंजीकृत एवं अवैध रूप से निर्मित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय विभिन्न निकायों द्वारा कार्यशालाओं में निर्मित लाखों अपंजीकृत ई-रिक्शाओं के बिना किसी मानक विनिर्माण प्रक्रिया या सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन किए चलने के बारे में दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर लिया गया।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारियों को स्थानीय गैराजों में गुप्त रूप से निर्मित बैटरी चालित अपंजीकृत ई-रिक्शा की पहचान करने तथा समयबद्ध तरीके से उन्हें हटाने को कहा गया है।

परिवहन सचिव सौमित्र मोहन ने 12 सितंबर को जारी एक नोटिस में कहा 'सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने के बाद मूल उपकरण निर्माताओं सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा विधिवत निर्मित ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों का पालन न करने के संबंध में विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।'

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार केवल अधिकृत एजेंसियां ही उत्पाद परीक्षण कर सकती हैं और प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती हैं।

इसमें कहा गया है 'यदि नए आवेदक सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, तो उन्हें आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर व्यापार लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे, जबकि पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रक्रिया 48 घंटों के भीतर पूरी करनी होगी।'

परिवहन विभाग के एक अन्य अधिकारी ने दावा किया कि वर्तमान में राज्य की सड़कों पर लगभग 2,00,000 अपंजीकृत ई-रिक्शा चल रहे हैं।

उन्होंने ऐसे सभी अपंजीकृत ई-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कोई समय नहीं बताया, लेकिन कहा कि 12 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

संयुक्त बस सिंडिकेट परिषद सहित कई बस ऑपरेटर निकायों ने राज्य परिवहन विभाग को ज्ञापन देकर कहा है कि ई-रिक्शाओं की बढ़ती संख्या के कारण कई बस मार्ग बंद हो गए हैं या कई मार्गों पर बस सेवाएं कम हो गई हैं।

संयुक्त बस सिंडिकेट परिषद के सचिव तपन बनर्जी ने कहा रहमने बार-बार राज्य सरकार से स्थिति पर गौर करने को कहा है। ई-रिक्शा के बढ़ते चलन के कारण लोकप्रिय मार्ग बंद हो गए हैं। कोलकाता के बाहर, ऐसे अवैध ई-रिक्शा के चलने से स्टेज कैरिज सेक्टर (बसें/मिनी बसें) में संकट पैदा हो गया है, जो नियमित करदाता हैं और सभी निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करते हुए अपने वाहन चलाते हैं।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने देहरादून में खोला ई-तिपहिया शोरूम

परिवहन विशेष न्यूज

देहरादून और आस-पास के इलेक्ट्रिक ऑटो लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा की पॉपुलर कंपनी ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने उत्तराखंड में ई-रिक्शा और ई-ऑटो ब्रांड की बिक्री वास्ते उत्तराखंड में अपनी प्रेजेंट्स बढ़ाते हुए पहला इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम सुभाष नगर चौक, सहारनपुर रोड में श्री राधे ऑटो के नाम से खोला है। कंपनी का कमिटमेंट है कि इलेक्ट्रिक थी-व्हीलर इंडस्ट्री में पहली बार कई पहलुओं के साथ बेहतरीन आफ्टर-सेल्स एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है।

ग्राहकों को श्री राधे ऑटो शोरूम आने में खास अनुभव मिलेगा और उन्हें ठुकराल इलेक्ट्रिक ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। देहरादून में ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के 3-व्हीलर नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे उत्तराखंड में ग्राहकों को सेल्स और आफ्टरसेल्स का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा।

ईवी के निर्माण से पीछे हट रहीं बड़ी ऑटो कंपनियां, देर से मार्केट में लॉन्च करेंगी वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका में इंटरनेशनल मार्केट की प्रमुख ऑटो निर्माता कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की गति धीमी कर दी है। हाल ही में बड़ी ऑटो कंपनी वोल्वो ने कहा है कि वह पूरी तरह से ईवी बनाने की अपनी योजना को तेजी से आगे नहीं बढ़ाएगी। इसी तरह जनरल मोटर्स और फोर्ड ने भी अपने पूर्व घोषित इलेक्ट्रिक मॉडल्स को पेश करने में देरी करने की बात कही है।

इसका असर केवल बड़ी कंपनियों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सैकड़ों अन्य कंपनियों पर भी पड़ेगा, जो इन बड़ी कंपनियों को विभिन्न प्रकार के सामान और पुर्जे सप्लाई करती हैं। ऑटो इंडस्ट्री के ट्रेड ग्रुप एमईएमए के एक सर्वे के अनुसार सप्लायर्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ऑटो कंपनियां अपनी पूर्व योजना के अनुसार ईवी नहीं बनाएंगी, तो इससे सप्लायर्स की स्थिति भी प्रभावित होगी। बड़ी कार कंपनियों की तुलना में सप्लायर्स और छोटी कंपनियों के पास पूंजी बहुत कम होती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इस बदलाव से लोगों के रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पिछले कुछ वर्षों में ऑटो सप्लायर्स ने लगभग नौ लाख लोगों को रोजगार दिया है। अमेरिका के 100 सबसे बड़े ऑटो सप्लायर्स में से 60 मिशिगन में स्थित हैं।

पिछले साल राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार ने 2032 तक दो तिहाई वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, इस साल सरकार ने अपने रुख को नरम कर दिया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी है, लेकिन खरीदारों का उत्साह ठंडा पड़ा है। एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस की बैटरी डिवीजन के अधिकारी टिम डीबेस्टोस ने कहा- 'एक साल पहले ईवी पर काम न करने को एक बड़ा मौका गंवाना माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें अब लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा।'

रूट बदला तो सीज होगा ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

हरदोई में ई-रिक्शा का रूट निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित रूट की अनदेखी ई-रिक्शा चालकों पर भारी पड़ सकती है। रूट व नियमों की अनदेखी करने पर 15 दिन में 215 ई-रिक्शे सीज किए जा चुके हैं।

शहर में यातायात को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शे का रूट निर्धारित कर दिया गया है। इसके लिए सभी ई-रिक्शा को यातायात पुलिस की ओर से नंबर जारी किए गए हैं, जिससे उनके रूट के विषय में जानकारी हो सके। इसके साथ ही ई-रिक्शा के चालक व स्वामी के विषय में भी रिकॉर्ड है। इससे अगर कोई घटना हो तो संबंधित ई-रिक्शा के विषय में जानकारी हो सकेगी। रूट निर्धारित होने के बावजूद अभी भी ई-रिक्शा चालक मनमानी कर रहे हैं और कई ई-रिक्शा चालकों ने अभी तक रूट के लिए नंबर नहीं लिया। इस पर यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। एक सितंबर से अब तक 215 ई-रिक्शों को सीज किया जा चुका है।

यातायात प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सही रहे और ई-रिक्शे के कारण जाम न लगे। इसलिए रूट निर्धारित कर दिए गए हैं। जो ई-रिक्शा चालक रूट की अनदेखी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

राज्य परिवहन निगम की बसें इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील होंगी, भारत सरकार ने शुरू की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

बढ़ते प्रदूषण की समस्या झेल रहे देश में परिवहन निगमों की बसों का पुराना बेड़ा भी बड़ी समस्या बना हुआ है। सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों की कमी से जूझ रहे तमाम राज्यों की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय चाहता है कि निगमों की जो बसें अभी संचालन के मानकों के अनुरूप फिट हैं, उनमें ईवी किट लगाने का विकल्प रखा जाए।

इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों से तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है। लगातार बढ़ रही वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में तो न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में अलग-अलग अवधि के वाहनों पर प्रतिबंध लगा भी है, लेकिन अमल को लेकर उतनी गंभीरता नहीं है।

केंद्र सरकार की चिंता पर्यावरण के साथ ही मानव जीवन को लेकर भी है, इसलिए पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए स्क्रैपिंग नीति पर जोर है। वर्तमान में भारत स्टेज- 6 यानी बीएस-6 श्रेणी के वाहन प्रदूषण के मानकों पर फिट घोषित हैं। बीएस-5 वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन उससे पुराने वाहन चिंता का सबब हैं। हालांकि सरकारी वाहनों को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं कि 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण नहीं होगा।

इसके बावजूद एक समस्या यह भी है कि राज्यों में बस बेड़ा अधिकतर पुराना ही है और सभी बसों को स्क्रैप करा देने की स्थिति नहीं है। हाल के वर्षों के एक अध्ययन के मुताबिक, परिवहन निगमों द्वारा संचालित की जा रही बसों की संख्या लगभग 2.8 लाख है, जबकि आबादी के अनुरूप आवश्यकता करीब 30 लाख बसों की है। ऐसे में विचार है कि पुरानी फिट बसों को पर्यावरण के मानकों के अनुरूप बनाकर संचालन में रखे जाने के विकल्प पर काम किया जाए।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन का कहना है कि आमजन को स्वयं पर्यावरण और मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए अनफिट वाहनों को स्क्रैप करा देना चाहिए, लेकिन सरकार इसे कैसे आगे बढ़ा सकती है, इस पर विचार चल रहा है।

उन्होंने बताया कि आटोमोबाइल कंपनियों के साथ इस संबंध में चर्चा की गई है। उनसे कहा है कि ऐसी तकनीक पर काम करें कि परिवहन निगमों की फिजिकली फिट पुरानी बसों के डीजल इंजन को निकालकर उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल किट लगाई जा सके। यह तकनीक सफल होती है तो पर्यावरण की सुरक्षा रहेगी और राज्य भी बस बेड़े के अधिक स्क्रैपिंग के भार से बच सकेंगे।

उत्तम पालन-पोषण: अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर ध्यान देना

विजय गर्ग

ऐसे युग में जहां पालन-पोषण निरंतर जांच के दायरे में रहता है, बच्चों के पालन-पोषण का तनाव आधुनिक समय के बोझ के रूप में विकसित हो गया है पुराने दिनों में, बड़े परिवारों में जन्म लेना और कई भाई-बहनों के साथ बड़ा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन किसी कारण से, उस समय माता-पिता इसे शांत दृष्टिकोण के साथ करते थे और परिवार के आकार के कारण उन्हें दबाव महसूस करते हुए नहीं सुना या जाना जाता था। मेरे नाना-नानी के 13 बच्चे थे और मेरे नाना-नानी के दस। आधुनिक समय में इस परिदृश्य की कल्पना करना भी असंभव है, जहां तनाव सभी के लिए एक प्रमुख समस्या बन गया है - किंडरगार्टन के बच्चों से लेकर किशोरावस्था के बाद पेंशनभोगियों तक। आज के माता-पिता अपेक्षाओं के बवंडर में फंसे हुए हैं, वे लगातार जीवन के अविश्वसनीय दबावों से जूझते हुए ?संपूर्ण? होने का भार महसूस करते हैं। यह विडंबना हममें से किसी से भी छिपी नहीं है - हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, माता-पिता अक्सर महसूस करते हैं कि वे कमजोर पड़ रहे हैं, एक ऐसे समाज द्वारा पिछड़ रहे हैं जो उन्हें असंभव मानकों पर रखता है। माता-पिता का तनाव एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव की आवश्यकता है। हमारी हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में, जहां हर कार्य और निर्णय सार्वजनिक जांच के अधीन है, पूर्णता की तलाश एक अंतहीन खोज है जो केवल थकावट की ओर ले जाती है। हमें रुककर पूछने की ज़रूरत है: क्या हम, माता-पिता के रूप में, खुद को एक ऐसे कोने में धकेल रहे हैं, जहाँ हमारा सर्वश्रेष्ठ कभी भी अच्छा नहीं हो पाता? हमें अपनी योग्यता साबित करने के लिए कितनी दूर तक जाना चाहिए और मुश्किल में पड़ने से पहले हम कितना तनाव झेल सकते हैं? एक युवा माता-पिता ने हाल ही में उल्लेख किया कि कैसे वह अपने बच्चे के कुछ साल बड़े होने का इंतजार कर रही थीं ताकि कठिन वर्षों के तनाव दूर हो जाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि पालन-पोषण का तनाव शायद ही कभी जाता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। हमेशा चिंतित रहना माता-पिता के मानस में है, चिंताएँ और अपेक्षाएँ उम्र के साथ बदलती रहती हैं। एक बार माता-पिता, हमेशा माता-पिता। आदर्श माता-पिता बनने के लिए एक अनवरत संघर्ष चल रहा है, जिन्होंने ऐसी अद्वितीय संतानें पैदा की हैं जिनकी दुनिया सराहना करेगी। पालन-पोषण की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का यह दबाव अब सोशल मीडिया द्वारा कई गुना बढ़ गया है जो पारिवारिक जीवन को आदर्श चित्र प्रस्तुत करता है।

माता-पिता अक्सर यह भूल जाते हैं कि बच्चों का पालन-पोषण करना कभी भी आसान नहीं होता है और सोशल मीडिया पर जो सही लगता है वह चुनौतियों से भरे जीवन और परिदृश्य का फ़िल्टर्ड संस्करण है। 'संपूर्ण माता-पिता' होने का विचार एक मिथक है और माता-पिता के लिए यह समझना समझदारी होगी कि समाज, मीडिया और साथियों द्वारा निर्धारित मानदंड अक्सर अप्राप्य होते हैं। प्रत्येक परिवार को अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं को अपने संसाधनों, परिस्थितियों और बच्चों की चारों ओर से अत्यधिक अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के अनुरूप निर्धारित करना चाहिए। पहले के माता-पिता अपने बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई चिंताओं और शिकायतों के बीच अपना ध्यान कैसे विभाजित करने में सक्षम रहे हैं, यह मुझे चकित करता है। हमारे परिवार में यह मजाक चलता रहता है - बच्चे अभी-अभी बड़े हुए हैं; किसी ने भी उन्हें कड़े मानकों का पालन करके बड़ा नहीं किया। यह रवैया हमारे समय में काम नहीं कर सकता है जहां मानदंड इतने ऊंचे हैं और उपलब्धि की दौड़ को इतनी गंभीरता से लिया जाता है कि माता-पिता बच्चों के बाद भी खुद को चिंता और चिंता के दलदल में फंसा हुआ पाते हैं। अपने घरों से उड़ गए हैं और अपना घोंसला बना लिया है। अपर्याप्त माता-पिता होने की चिंता कई लोगों को सताती है और सच तो यह है कि माता-पिता बनने का कोई एक सही तरीका नहीं है; न ही बच्चों को सफल बनाने का कोई निर्धारित प्रारूप हैऔर उनमें सही मूल्यों को स्थापित करने के अलावा खुश हैं। माता-पिता के रूप में अपनी खामियों को स्वीकार करना और उन्हें छोड़ना सीखना, माता-पिता बनने की उनकी यात्रा में अपनाने के लिए कठिन लेकिन आवश्यक गुण हैं। बच्चों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह एक ऐसे माता-पिता की नहीं होती जिसके पास सब कुछ होता है, बल्कि एक ऐसे माता-पिता की होती है जो उन्हें प्यार करता है, उनका समर्थन करता है और जीवन के उतार-चढ़ाव में मौजूद रहता है। बच्चों के बारे में लगातार चिंता करने से बच्चों का आत्मविश्वास ही खत्म हो जाएगा और वे जीवन की असंख्य चुनौतियों का सामना करने में अक्षम हो जाएंगे।

एआइ की व्यापकता के बीच हिंदी का भविष्य

वर्ष 2022 में 30 नवंबर वह तिथि है, जब कृत्रिम बुद्धिमता के इतिहास में एक नया आयाम इस रूप में दर्ज हो गया कि इस दिन से इंटरनेट एक नए अवतार में सामने आ गया। चैटजीपीटी ओपनएआइ द्वारा लांच एक चैटबाट ने विश्व को वह राह दिखाई कि गूगल द्वारा खोज कर प्रस्तुत की जा रही समग्री से कितनी वह अधिक उपयोगी हो सकती है। शिक्षा, चिकित्सा, भ्रमण, कापीराइटिंग, कानून से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बच्चा है, जहां चैटजीपीटी और उसके बाद गूगल के जेमिनी एआई (पूर्व में बार्ड) जैसे तमाम नए मंच ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि मशीनें लगभग मानव जितनी समझदार हो सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमता के बल पर वे केवल बराबरी नहीं कर सकती हैं, बल्कि कुछ मामलों में बेहतर भी हो सकती हैं।

इससे पहले कि हम एआइ के दायरे में हिंदी के हस्तक्षेप और अंग्रेजी के वर्चस्व की और से मिलने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें, देखना होगा कि इस मामले में हमारी सरकार क्या कर रही है। वह तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाने वाली राजभाषा हिंदी का किस रूप में उपयोग कर रही है। इसका एक उदाहरण भारत सरकार की प्रौद्योगिकी भागीदार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की साइट से मिलता है। इसके पहले पेज पर लिखा है, 'एआइ मशीनें द्वारा मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण है। यह प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है और आइटी सिस्टम में संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग को लागू करके मानव बुद्धि को अनुकरण करना इसका लक्ष्य है।'

निश्चय ही हिंदी का आज का पाठक इस तरह की कठिन भाषा का पक्षधर नहीं हो सकता है। संभव है कि भाषा की इस दुरूहता के बारे में सचेत करने पर यह विभाग इस दिशा में सुधार के कुछ प्रयास करेगा। एक अन्य उदाहरण दे साल पहले 2022 में राजभाषा पर बनाई गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की संस्तुतियों का लिया जा सकता है। इस समिति ने अक्टूबर 2022 में संस्तुति की थी कि हिंदी भाषी राज्यों में आइआइटी जैसे तकनीकों और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय भाषा होनी चाहिए। इसके साथ ही, अंग्रेजी का उपयोग वैकल्पिक होना चाहिए। समिति ने यह संस्तुति भी की थी कि हिंदी को संयुक्तराष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होना चाहिए। समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब के अनुसार, समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये सार सुझाव दिए थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी का केवल 20-30 प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के क्षेत्र में हिंदी अपनी कोई हैसियत बना पाएगी।

इस सवाल का अभी आशाजनक उत्तर देना कठिन हो सकता है, परंतु इसकी तकनीक में वह जवाब छिपा है जो एआइ में हिंदी के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है। असल में, एआइ एक तकनीक नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) की तरह इसे भाषा विज्ञान से जोड़ने वाला नय आविष्कार है यह एक ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से हम मनुष्यों को नैचुरल लैंग्वेज का उपयोग करते हुए मशीनों रोबोट्स से संवाद करने में मदद मिलती है। इस तरह का एक उदहरण गूगल बाइस सर्च है, जोकि नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करता है। इसका अभिप्राय यह है कि आप इसे जिस भाषा में संवाद करने के हिसाब से विकसित करेंगे, यह तकनीक इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों में से बेहतर का चुनाव करते हुए उसी भाषा में उत्तर उपलब्ध कराएगे यानी एआइ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सवाल या जिज्ञासा किस भाषा में उसके सामने रखी। गई है। वह सवाल के अनुकूल इसकी खेज करती है कि क्या संबंधित भाषा के अलावा अन्य भाषाओं (जैसे कि हिंदी में पूछे गए सवाल के जवाब हिंदी के अलावा अंग्रेजी आदि) में उपलब्ध हैं या नहीं। यदि वे सामग्रियां वहां मौजूद हैं, ती एआइ तुरंत सभी समग्रियों को संयोजित करते हुए हिंदी या अन्य भाषा में समाधान प्रस्तुत कर देती है एआइ ऐसा किस प्रकार कर पाती है, इसका जवाब इसमें निहित है कि एआइ असल में मशीनों के सीखने की प्रक्रिया (मशीन लर्निंग) का एक मुख्य अवयव है। मशीन लर्निंग की यह प्रक्रिया गूगल सूर्य की तुलना में इसलिए थोड़ी अलग है, क्योंकि इसके तहत कंप्यूटरीकृत साफ्टवेयर स्वयं किए गए कार्यों से मिलने वाले अनुभवों से लगातार सीखते और उसी के अनुसार उसमें सुधार करते जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बार जिस भाषा में संवाद किया जा चुका है, उस भाषा में सीखे गए नए शब्दों, उद्धरणों को अगले उत्तरों में सम्मिलित कर लिया जाता है। कह सकते हैं कि एआइ से संबंधित मशीन लर्निंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर साफ्टवेयर स्वयं को ही प्रशिक्षित करते रहते हैं। चूंकि पैटजीपीटी और जैमिनी (बार्ड) जैसे कृत्रिम बुद्धिमता के टैल्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग, दोनों का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं, जैसे हिंदी में मिलने वाले उत्तरों में हर दिन सुधार होता जाएगा। इस आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि एआइ में हिंदी का भविष्य उज्जवल ही है। इसमें यदि कोई बाधा है तो केवल यह कि तकनीक प्रौद्योगिकी से जुड़े संगठनों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई और शोध कार्यों में हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जिस दिन से वहां ऐसा किया जाने लगेगा, एआइ के माथे पर हिंदी की बिंदी पूरी प्रखरता के साथ चमकने लगेगी।

-विजय गर्ग

ज्ञान

देवभूमि को देवभूमि बनाए रखिए

शिमला के संजौली में भडक़े उग्र आंदोलन के बाद मुस्लिम नेताओं ने मस्जिद के अवैध निर्माण को स्वयं गिराने का आवेदन नगर निगम को देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। मंडी में तो मस्जिद परिसर में अवैध निर्माण को खुद मुसलमानों ने तोड़ दिया। इसके बावजूद हिमाचल लामबंद है। अन्य जिलों में भी वर्ग विशेष द्वारा कथित अवैध कब्जों और निर्माणों को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। शक के दायरे में पूर्ववर्ती भाजपा और वर्तमान कांग्रेस सरकार, दोनों हैं। पिछले दो दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में वर्ग विशेष के लोगों का आकर बसना और मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों की तामीर कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। अब सवाल उठ रहे हैं कि संजौली की मस्जिद में चार मंजिलों के अवैध निर्माण की अनुमति भाजपा सरकार के दौरान किसने दी और उसके लिए धन कहां से आया? उस दौरान और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई शिकायतों पर नगर निगम ने कार्रवाई क्यों नहीं की? शिमला समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में आ रहे लोगों द्वारा बनाई और संचालित की जा रही मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे भी अब सवालों के घेरे में हैं। जांच का विषय यह भी है कि इनके लिए धन कहां से आया। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से प्रवासी आते रहे हैं। अंग्रेजों के दौर से लेकर आज तक शिमला और कांगड़ा जिलों में कश्मीरी मुसलमान मजदूरी के लिए आते हैं।

स्थानीय लोग उन्हें सम्मान से 'खान साहब' कह कर बुलाते हैं और उनके साथ सांप्रदायिक विवाद की नौबत कभी भी नहीं आई। हिमाचली समाज सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। सदियों से प्रदेश में बसे मुसलमानों और स्थानीय हिंदुओं के बीच भी सौहार्द रहा है। चंबा के पारंपरिक मिंजर मेले के धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन मुसलमान मिर्जा परिवार के योगदान के बिना पूरे नहीं हो सकते। नाहन में श्री जगन्नाथ यात्रा एवं अन्य हिंदू धार्मिक पर्वों पर स्थानीय मुसलमानों का सहयोग रहता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पड़ोसी राज्यों एवं बिहार आदि अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों का यहां आकर बसना और मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों का निर्माण किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। स्थानीय मुसलमानों की छोटी सी आबादी के लिए किन्नौर और लाहुल-स्पीति को छोडक़र प्रदेश के 10 जिलों में लगभग 550 मस्जिदें, 30 से अधिक मदरसे, 28 मरकज और 450 से अधिक मौलवियों की फौज बाहरी मुसलमानों की नीयत पर शक पैदा करती है। विभिन्न जिलों में समय-समय पर पैदा होने वाले सांप्रदायिक तनाव प्रदेश के इतिहास में बिल्कुल नया अध्याय है। शिमला एवं अन्य क्षेत्रों में बाहरी मुसलमान दुकानदारों द्वारा स्थानीय लोगों के हक पर चोट की जा रही है। यह लोग सडक़ों के किनारे फल और सब्जी के अलावा अन्य कई प्रकार का व्यवसाय अवैध तौर पर करते हैं। सरकार के पास प्रवासियों के पंजीकरण और रेहड़ी-फड़ी लगाने के लाइसेंस देने की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उनके कारोबार से सडक़ों पर ट्रैफिक में व्यवधान आता है और बड़े स्तर पर टैक्स की चोरी भी की जाती है। स्थानीय व्यापारियों को भी इनसे नुकसान होता है। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों द्वारा या तो इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया अथवा चुप्पी साध ली गई। राजनेताओं को बाहरी मुसलमानों में अपना वोट बैंक भी दिखता है। उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड हाथों-हाथ बनवा दिए जाते हैं। उनके अवैध कब्जों पर हुए निर्माण में बिजली-पानी के कनेक्शन भी दे दिए जाते हैं।

अन्य राज्यों की तरह ही हिमाचल प्रदेश का वक्फ बोर्ड भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। संजौली मस्जिद के मामले का उदाहरण ही स्थितियों को स्पष्ट करता है। विधानसभा में ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध ढंग से सरकारी जमीन पर किया गया है। नगर निगम पहले किसी सलीम नामक व्यक्ति को नोटिस भेजता था। अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि जमीन बोर्ड की है। लेकिन अवैध निर्माण किसने किया, इसका इल्म उसे नहीं है! जांच तो इस मामले की भी होनी चाहिए कि सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास कराए पांच मंजिला मस्जिद बनाने के लिए आए धन का स्रोत क्या है? आसपास रहने वाली महिलाएं कैमरे पर कह रही हैं कि मस्जिद में उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के मुसलमान रहते हैं और उनसे छेड़छाड़ करना रोजमर्रा की बात है। शिमला के ही कुसुंपटी में अवैध मस्जिद का विवाद वर्षों से चल रहा है। वहां बाहरी मुसलमान जाकर नमाज पढ़ते हैं जबकि क्षेत्र में मुस्लिम आबादी शून्य है। ईदगाह क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए मकानों को बिजली-पानी की सुविधा मिली हुई है। स्थानीय लोग इसे लैंड जिहाद का नाम देते हैं। दूसरे राज्यों से तबलीगी जमातों के रूप में यहां आने वाले मुस्लिम जत्थे बाहरी और स्थानीय मुसलमानों को कट्टरता का पाठ पढ़ाकर हिंदुओं के प्रति नफरत का जहर घोलते हैं।

कृषि सुधारों से बढ़ती आर्थिकी

हम उम्मीद करें कि तीन सितंबर को सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली जिन सात योजनाओं तथा 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्मों से किसानों की आय बढ़ाने की जो पहल की है, उसके लाभों और प्रयोग के बारे में किसानों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में बेहतर बदलाव का परिदृश्य है'

हाल ही में प्रधानमंत्री की अगुआई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 14000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 2817 करोड़ रुपए डिजिटल कृषि मिशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं फसल विज्ञान पर 3979 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2291 करोड़ रुपए के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड़ रुपए के प्लान को मंजूरी दी गई है। पिछले कुछ समय से जीडीपी में कृषि का योगदान घट रहा था। लेकिन मोदी सरकार की हालिया पहल से कृषि क्षेत्र और किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सात योजनाएं कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और कृषि उन्नयन के प्रयासों से आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 3 सितंबर को विश्व बैंक के द्वारा जारी 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार व ग्रामीण मांग में तेजी के चलते भारत की विकास दर 7 फीसदी के स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई देगी। रिपोर्ट में वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। मानसून में सुधार, निजी खपत व बढ़ते निर्यात से भी भारतीय जीडीपी को मजबूती मिल रही है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि सरकार को इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासत में मिला है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। पूरे देश के कोने-कोने में बेहतर मानसून के लाभ दिखाई देने लगे हैं। बेहतर मानसून से ग्रामीण इलाकों में खपत तेजी से बढ़ रही है।

बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। ऐसे में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिक खर्च कर रहे हैं। कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, वरन गांवों में उपभोक्ताओं की खरीददारी भी उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है। निःसंदेह सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना समय की मांग है। सरकार के द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों प्रकाशित हो रही वैश्विक आर्थिक संगठनों और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों में भारत में कृषि सेक्टर में सुधार और ग्रामीण खपत में वृद्धि के मद्देनजर भारत की विकास दर के अनुमान बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 व 2026-27 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। इसी तरह भारत की विकास दर के अनुमानों को ओईसीडी ने 6.2 से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 6.3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत तथा फिच ने 7 से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया है। इसमें कोई दोमत नहीं हैं कि देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने का रणनीतिक अभियान आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के अभियान के तहत 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। इस बजट के माध्यम से कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए 10000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जहां इस कोष का उपयोग दाल, प्याज और आलू के बफर स्टॉक को रखने के लिए किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की डगर पर आगे बढ़ते हुए कई अहम बातों पर ध्यान दिया जाना होगा। सरकार के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सडक़ों को मंडियों से जोडऩे जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को नियंत्रित रखने के कारगर प्रयासों की डगर पर लगातार आगे बढऩा होगा। चूंकि देश में फसल कटाई के बाद की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसे में बजट के तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए जिस तरह खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए ऋणों की राशि दोगुनी सुनिश्चित की गई है, उसके कारगर उपयोग पर ध्यान देना होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार कृषि भंडारण क्षमता वर्ष 2023 में 14.5 करोड़ टन थी। अब उसे वर्ष 2030 तक दोगुना बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढऩा होगा।

कृषि भंडारण क्षमता के भौगोलिक स्तर पर उचित वितरण की डगर पर भी सरकार को आगे बढऩा होगा। जहां उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तो अधिक भंडारण क्षमता है, वहीं बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में इसकी भारी कमी है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में केवल एक ही फसल रखने की व्यवस्था होती है। अन्य फसलों के भंडारण की सुविधा इनमें नहीं होती। इसलिए अब देश भर में भंडारण क्षमता को उन्नत कर इनमें सभी या एक से अधिक कृषि उपज रखने की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना होगा। हम उम्मीद करें कि तीन सितंबर को सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली जिन सात योजनाओं तथा 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्मों से किसानों की आय बढ़ाने की जो पहल की है, उसके लाभों और प्रयोग के बारे में किसानों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के नए बजट से कृषि और ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के जो रणनीतिक कदम बताए गए हैं, उनके क्रियान्वयन पर शुरुआत से ही ध्यान दिया जाएगा। इन सबके साथ-साथ सरकार के द्वारा बेहतर मानसून की शक्ति को मु_ी में लेकर कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे में जहां छोटे किसानों व ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों की खुशियां बढ़ेंगी, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगी।

बदलाव की राह

विजय गर्ग

कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपनी राह पर चल रहा है और एक नन्ही चींटी उसके पैरों के नीचे आ जाती है, लेकिन नाक की सीध में चल रहे इंसान को शायद ही जमीन पर चल रही चींटी नजर आती है और वह उसे कुचलता हुआ आराम से आगे निकल जाता है। निरीह चींटी की करुण आवाज या उसका कमजोर विरोध उसे कभी नहीं दिखता है। कारण कि इंसान उस चींटी से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसे चींटी से किसी भी तरह के खतरे का डर नहीं होता। ठीक इस दृश्य के विपरीत यही इंसान जब किसी हिंसक जानवर के चंगुल में फंस जाता है तो उसे अपनी जान और खुद को सुरक्षित रखने के लिए किए गए विरोध की कीमत का पता चलता है। दरअसल, जब कुछ हमारी सहमति के विपरीत हो रहा होता है तो हम अपनी तरफ से उस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। किसी बात या घटना का विरोध करना, उसके खिलाफ जाना या उसे रोकने के लिए एक कड़ी लड़ाई लड़ना है, जिसे हर शख्स अपनी ताकत भर जरूर लड़ता है। अपने साथ हो रही किसी भी विपरीत घटना के खिलाफ विरोध करना हर जीव का अधिकार है। में हुए निर्भया दिल्ली में 2012 कांड को शायद ही किसी ने भुलाया होगा। आज इस घटना के बारह वर्ष होने के बाद भी माहौल कुछ खास नहीं बदला है जब देश के अलग-अलग हिस्सों से इसी तरह की हृदय विदारक घटनाएं घटित हो रही हैं। इनके विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या विरोध प्रदर्शनों की सीमा केवल जख्मों पर मरहम लगाने तक ही सीमित है या ये प्रभावी भी होते हैं ? निर्भया कांड के बाद दिल्ली सहित देश के बाकी हिस्सों में भी तब खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरे थे। निर्भया कांड के बाद हुए इन विरोध प्रदर्शनों ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ दिया था।

इसने प्रशासन और समाज को यह समझने के लिए मजबूर किया था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जनता के विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को सख्त बनाने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013, को पारित किया, जिसे आमतौर पर निर्भया कानून कहा जाता है। इस कानून के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान किया गया, जिसमें मौत की सजा भी शामिल है। इस घटना के बाद 2015 में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे गंभीर अपराधों में शामिल पाए जाने वाले सोलह से अठारह वर्ष के किशोर अपराधियों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया। निर्भया कांड के बाद ही त्वरित अदालतों की स्थापना भी की गई, ताकि यौन अपराधों से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

इन सभी साक्ष्यों के बावजूद क्यों बहुत से लोग इस बात पर आश्वस्त हैं कि विरोध प्रदर्शन अप्रभावी होते हैं? इसका एक संभावित कारण यह है कि विरोध के पीछे कई अंतर्निहित उद्देश्य- शोषण, नस्लवाद, पितृसत्ता और लोकतंत्र की खराब गुणवत्ता - प्रणालीगत समस्याएं हैं। विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वालों को अक्सर संदेह और ऐसे सवाल का सामना करना पड़ता है- 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो परेशान क्यों होना ?'

यह सही है कि विरोध प्रदर्शन से समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन यह समाज में एक महत्त्वपूर्ण संदेश भेजने और परिवर्तन की दिशा में कदम उठाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। विरोध प्रदर्शन काम करते हैं, क्योंकि हम लगातार ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां विरोध से फर्क आया है। हमने 2024 में ही देखा है कि फ्रांस के किसानों द्वारा नाकेबंदी और विरोध प्रदर्शन ने सरकार को रियायतें देने के लिए प्रेरित किया है। इसी तरह, भारत में, दिल्ली की ओर बढ़ रहे नए किसान आंदोलन से पहले ही सरकार ने फसलों के लिए बेहतर कीमतों की पेशकश की। बुडापेस्ट में बाल यौन शोषण कांड को लेकर सड़कों पर हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण कुछ समय पहले इस कांड को संबोधित करने के लिए कानून पेश किया गया। पिछले वर्ष के अंत में पनामा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और सड़कों पर नाकेबंदी के कारण वहां की सरकार को दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से एक को बंद करना पड़ा। अगर कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआइ से जल्द से जल्द स्थिति रपट मांगना कहीं न कहीं इन प्रदर्शनों की वजह से ही संभव हुआ है ,विरोध प्रदर्शनों का होना इस बात का भी संकेत होता है कि जनता को वर्तमान स्थिति पसंद नहीं है और वह इसके खिलाफ खड़े होने का साहस कर सकती है। कई बार यह पीड़ितों और उनके परिवारों को मानसिक और भावनात्मक रूप से समर्थन प्रदान कर मजबूती से खड़ा होने में मदद करता है। इससे उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करने का हौसला मिलता है। यह कई बार देखने को मिला है कि बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों से सरकार और प्रशासन पर दबाव बनता है, जिससे वे अधिक कठोर कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए चाहे छोटी हो या बड़ी, हर गलत बात के लिए विरोध करने का साहस होना चाहिए।

रिन्यूएबल एनर्जी में आएगी क्रांति, 32.45 लाख करोड़ का कर्ज देंगे बैंक

परिवहन विशेष न्यूज

ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गांधीनगर में आयोजित चौथे री-इन्वेस्ट कार्यक्रम में कहा कि मैं सभी हितधारकों को भारत के जीवंत और तेजी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है आपके निवेश को हमारे बढ़ते प्रभाव और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से लाभ होगा।

नई दिल्ली। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को निवेशकों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित परियोजनाओं के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की प्रतिबद्धता जताई है। चौथे 'री-इन्वेस्ट 2024' कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा, 'हमें 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही डेवलपर, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से भारी प्रतिबद्धताएं मिली हैं।'

सीआईआई के साथ साझेदारी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा री-इन्वेस्ट का आयोजन कर रहा है। उन्होंने बताया कि डेवलपर ने अतिरिक्त 570 गीगावाट क्षमता जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स ने सौर मॉड्यूल में 340 गीगावाट, सौर सेल में 240 गीगावाट, पवन टरबाइन में 22 गीगावाट और इलेक्ट्रोलाइजर में 10 गीगावाट की अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता की प्रतिबद्धता जताई है। बैंक और वित्तीय संस्थानों ने 2030 तक 386 अरब डालर (32.45 लाख करोड़ रुपये) के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

अक्षय ऊर्जा क्षमता 207.7 गीगावाट हुई

जोशी ने कहा, "मैं सभी हितधारकों को भारत के जीवंत और तेजी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं।" उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, आपके निवेश को हमारे बढ़ते प्रभाव और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदलें और भारत की अपार संभावनाओं का दोहन करें।

उन्होंने कहा कि हमारी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 75.52 गीगावाट से बढ़कर अब 207.7 गीगावाट से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि यह पिछले 10 वर्षों में 175 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि है। मंत्री ने बताया कि 2014 से अब तक भारत में कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन 86 प्रतिशत बढ़कर 193.50 अरब यूनिट से 360 अरब यूनिट पर पहुंच गया है।

अदाणी ग्रुप करेगा 4.05 लाख करोड़ का निवेश

अदाणी समूह ने सोमवार को कहा कि उसने चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (री-इन्वेस्ट) 2024 के दौरान सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 4,05,800 करोड़ रुपये निवेश करने का संकल्प लिया है। समूह की कंपनियों-अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) और अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) ने 2030 तक नवीकरणीय परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी ने 2030 तक 50 गीगावाट क्षमता (वर्तमान में 11.2 गीगावाट परिचालन क्षमता) हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज 10 गीगावाट का सौर विनिर्माण संयंत्र, पांच गीगावाट का पवन विनिर्माण, 10 गीगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और पांच गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। इन निवेश से 71,100 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

64 हजार करोड़ का निवेश करेगी टोरेंट पावर

टोरेंट पावर ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 64 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया। इन परियोजनाओं की स्थापना से 26 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीदह है। टोरेंट पावर ने सोमवार को गुजरात के द्वारका में 5 गीगावाट सौर, पवन या सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना के लिए गुजरात सरकार के साथ एक एमआयू पर हस्ताक्षर किए।

होम लोन जल्दी खत्म करना चाहते हैं? इन उपायों पर करें अमल

परिवहन विशेष न्यूज

Home Loan Early Clearance होम लोन की अवधि अमूमन काफी लंबी होती है। इसलिए उसे जल्दी खत्म करने की टेंशन हर किसी को होती है। लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता कि होम लोन को जल्दी कैसे खत्म करें। हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने होम लोन को जल्द से जल्द चुका सकते हैं।

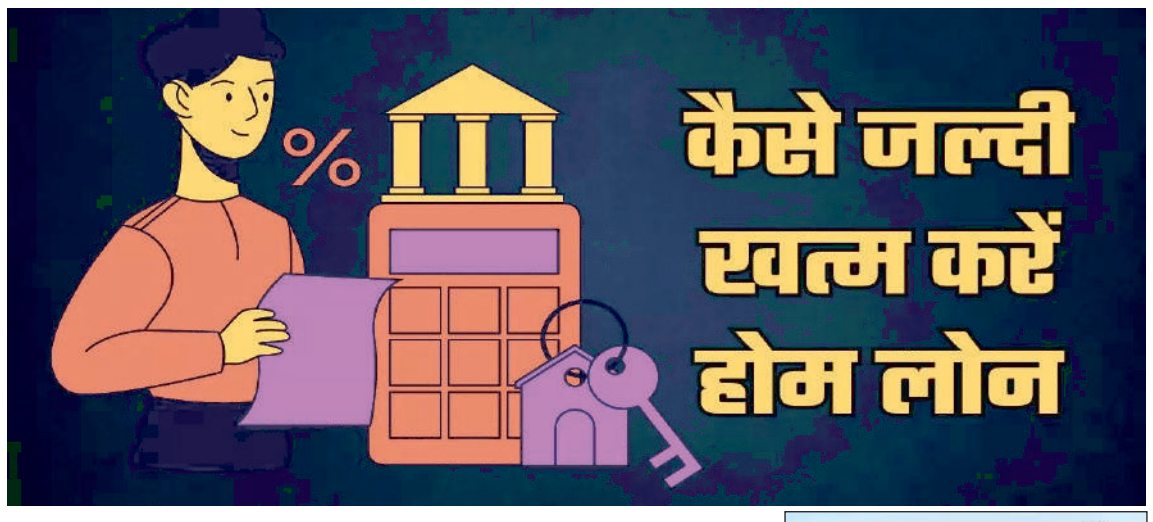

नई दिल्ली। अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अक्सर होम लोन (Home Loan) भी लेते हैं। चूंकि, होम लोन की रकम काफी बड़ी होती है। इसकी मासिक किस्त (EMI) को लंबे वक्त तक चुकाया जाता है। इसमें कई तरह के जोखिम और अनिश्चितता भी रहती है। ऐसे में आप लोन को जितनी जल्दी खत्म कर सकें, उतना ही अच्छा होगा। हम कुछ उपाय बता रहे हैं, जिन पर अमल करके आप होम लोन जल्दी खत्म कर सकते हैं।

होम लोन की अवधि कम करें

अगर आप कम समय में होम लोन खत्म करना चाहते हैं, तो प्री-पेमेंट का विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास जब भी बोनस या अन्य किसी अन्य माध्यम एकमुश्त बड़ी रकम आए, तो उसका इस्तेमाल होम लोन के प्री-पेमेंट के लिए करें। इससे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा और कर्ज की अवधि और EMI, दोनों में कमी आ सकती है। इससे आपको दोतरफा फायदा होगा। लोन की अवधि कम होने से आपकी टेंशन कम होगी, और आपको बैंक को ब्याज भी कम चुकाना पड़ेगा।

EMI बढ़वाना भी असरदार

अगर आपका प्रमोशन होता है या नौकरी बदलने पर अच्छा पैकेज मिलता है, तो आप EMI की रकम भी बढ़वा सकते हैं। EMI बढ़वाने से आप कर्ज का बोझ जल्दी उतार सकते हैं। कई बैंक हर साल इंस्टॉलमेंट रिवाइज करने का ऑप्शन देते हैं। अगर आपकी सैलरी में इजाफा हुआ है, तो आप इसका फायदा उठाकर अपने होम लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं।

लोन ट्रांसफर का विकल्प चुनें

आपको समय-समय पर अपने लोन की ब्याज दरों की दूसरे बैंकों की दरों के साथ तुलना करनी चाहिए। अगर आपका बैंक अधिक ब्याज दर ले रहा है, तो उससे ब्याज दर कम करने के लिए बात करें। अगर वह नहीं मानता, तो आप उस बैंक में लोन ट्रांसफर करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जो लोन पर कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इस बारे में आप किसी वित्तीय सलाहकार की राय भी ले सकते हैं।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ निवेशक मालामाल, लिस्टिंग पर ही डबल हुए पैसे; अपर सर्किट भी लगा

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इस आईपीओ ने भी निवेशकों को निराश नहीं किया और निवेशकों को 114 फीसदी का लिस्टिंग गेन दिया। यह आईपीओ 70 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर आया था। आइए जानते हैं कि क्या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के होल्ड करना चाहिए।

नई दिल्ली। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को निवेशकों को शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। इसने आईपीओ सब्सक्रिप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने भी इनवेस्टर को निराश नहीं किया और उन्हें 114 फीसदी का शानदार लिस्टिंग गेन दिया। इसका मतलब कि आईपीओ निवेशकों का पैसा पहले ही दिन डबल हो गया।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 70 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर आया था। यह 150 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसका मतलब कि आईपीओ निवेशकों को 114.29 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला। साथ ही, इसमें 10 फीसदी का अपर सर्किट लगा। यह 165 रुपये पर बंद हुआ। इसका मतलब कि एक लॉट भी खरीदने वाले निवेशकों को 20,000 हजार रुपये से अधिक का प्रॉफिट हो चुका है।

Bajaj Housing Finance : प्रॉफिट बुक या होल्ड करें?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मामले में एक्सपर्ट काफी आशावादी हैं। उनका मानना है कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। साथ ही, हाउसिंग सेक्टर का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। यह सेक्टर अगले 3-4 साल के दौरान अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रख सकता है, जिसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस को फायदा मिलेगा। हालांकि, एक्सपर्ट ने शॉर्ट टर्म निवेशकों को प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी। साथ ही, नए निवेशक एंट्री के लिए थोड़ा करेक्शन का इंतजार कर सकते हैं।

Bajaj Housing Finance IPO को मिला था जबरदस्त रिस्पॉन्स

बजाज ग्रुप की बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईपीओ के जरिए 6,560 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बनाया था। लेकिन, उसे 3.24 लाख करोड़ रुपये की बिड मिली। यह आईपीओ तकरीबन 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल इनवेस्टर्स (RII) के लिए रिजर्व हिस्सा 7.04 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 209.36 गुना और NII के लिए रिजर्व हिस्सा 41.51 गुना सब्सक्राइब हुआ। Bajaj Housing Finance IPO का GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग से पहले ही शानदार लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा था।

सभी शहरों के लिए अपडेट हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल कराने से पहले जानें लेटेस्ट प्राइस

Petrol-Diesel Latest Price तेल कंपनियों ने आज यानी 16 सितंबर के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट कर दिये हैं। हर रोज सुबह 6 बजे इनकी कीमत अपडेट होती है। ऐसे में गाड़ीचालक को सलाह दी जाती है कि वह लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही टंकी फुल करवाएं। आइए जानते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर मिल रहा है।

नई दिल्ली। देश की मुख्य तेल कंपनियां जैसे- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 16 सितंबर 2024 (सोमवार) के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है।

नए अपडेट के अनुसार आज भी सभी शहरों में तेल के दाम जस के तस बने हुए हैं। इसका मतलब है कि गाड़ीचालक पुरानी कीमत पर तेल खरीद सकते हैं।

सभी शहर में अलग है दाम

महानगरों और बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अलग होते हैं। इसकी वजह वैट (Vale Added Tax) है। दरअसल, फ्यूल प्राइस पर जीएसटी की जगह वैट लगाया जाता है। वैट की दरें राज्य सरकार तय करती है। ऐसे में हर राज्य में वैट की दर अलग होती है, जिस वजह से सभी शहरों में इसके दाम भी अलग होते हैं।

HPCL की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 16 September 2024)

चावल कंपनियों के शेयरों में उबाल; एक में अपर सर्किट, बाकियों में भी तगड़ा उछाल

परिवहन विशेष न्यूज

Rice Stocks केंद्र सरकार ने बासमती चावल के नियम पर 950 डॉलर प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) का कैप लगा रखा था। इसका मतलब कि चावल कंपनियां बासमती का निर्यात इससे कम कीमत पर नहीं कर सकती हैं। अब सरकार ने MEP हटा लिया है। इससे चावल कंपनियों को निर्यात के मोर्चे पर फायदा मिल सकता है। इससे चावल कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है।

नई दिल्ली। चावल कंपनियों के शेयर (Rice Stocks) में सोमवार को जबरदस्त तेजी दिखी। कोहिनूर फूड्स (Kohinoor Foods) में 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा। वहीं, चावल के कारोबार से जुड़ी अन्य कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली।

राइस स्टॉक्स में तेजी की वजह

केंद्र सरकार ने बासमती चावल के नियम पर 950 डॉलर प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) का कैप लगा रखा था। इसका मतलब कि चावल कंपनियां बासमती का निर्यात इससे कम कीमत पर नहीं कर सकती हैं। अब सरकार ने MEP हटा लिया है। इससे चावल कंपनियों को निर्यात के मोर्चे पर फायदा मिल सकता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि इस फैसले से चावल का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। 2022-23 में भारत का बासमती चावल का कुल निर्यात मूल्य के लिहाज से 4.8 अरब डॉलर रहा। वहीं, मात्रा के लिहाज से यह 45.6 लाख टन था।

किन स्टॉक्स में कितनी तेजी?

राइस स्टॉक्स की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी कोहिनूर फूड्स (Kohinoor Foods) में दिखी। यह 20 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 46.83 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, एलटी फूड्स 9.72 फीसदी, केआरबीएल 7.67 फीसदी और चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स 5.92 फीसदी उछला।

सरकार ने अब MEP को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इससे निर्यातकों को बासमती चावल की बढ़ती मांग दिखाई दे रही है। साथ ही, बासमती चावल की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, चावल कंपनियों के शेयरों में तेजी पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से है। कंपनियों ने पिछली अर्निंग कॉल में ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि बासमती चावल के निर्यात के लिए औसत प्राप्ति पहले से ही न्यूनतम निर्यात मूल्य से अधिक है।

अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 8 फीसदी तक उछले, जानिए क्या है वजह

Adani Power stocks अदाणी पावर और अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में सोमवार (16 सितंबर) को शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 8 फीसदी तक उछाल देखने को मिला। अदाणी ग्रुप की इन दोनों कंपनियों ने महाराष्ट्र स्टेट डिस्कॉम (MSEDCL) से 6600 मेगावाट (MW) हाइब्रिड (सोलर और थर्मल) पावर सप्लाई के लिए एक समझौता किया है। इस एग्रीमेंट का असर दोनों कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा।

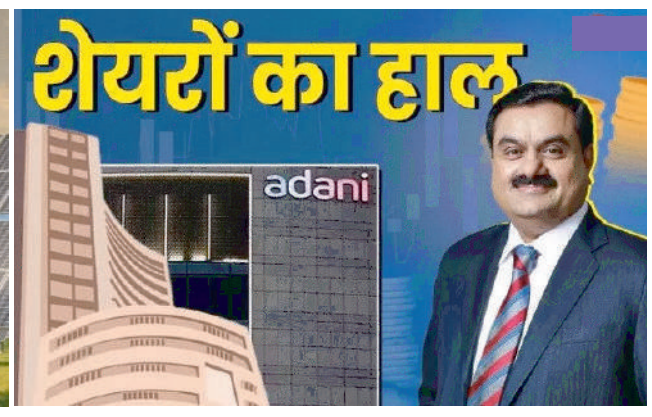

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के ग्रुप की पावर और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अदाणी पावर के शेयर (Adani Power Share) शुरुआती कारोबारी 8 फीसदी तक उछल गए। दरअसल, अदाणी ग्रुप ने महाराष्ट्र को लंबी अवधि में 6,600 मेगावाट बंडल रिन्यूएबल और थर्मल पावर की सप्लाई के लिए बोली जीत है।

अदाणी ग्रुप ने 4.08 रुपये प्रति यूनिट की बिड लगाई और जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ा। दोपहर करीब 2.30 बजे तक अदाणी पावर के शेयर 5.90 फीसदी उछाल के साथ 670.85 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। वहीं, अदाणी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक (Adani Green Energy Share Price) में करीब 8 फीसदी का उछाल दिखा। यह शुरुआती कारोबार में 7.39 प्रतिशत बढ़कर 1,920 रुपये पर पहुंच गया था।

दोनों कंपनियां करेंगी पावर सप्लाई

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अदाणी पावर महाराष्ट्र सरकार को अगले 25 साल के लिए बंडल रिन्यूएबल और थर्मल पावर सप्लाई करेगी। महाराष्ट्र सरकार अभी बिजली खरीदने के लिए जो लागत देती है, अदाणी ग्रुप की बोली उससे करीब एक रुपया कम है। इस प्रक्रिया से महाराष्ट्र को भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आशय पत्र दिए जाने की तारीख से 48 महीनों में आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

अदाणी पावर नई 1,600 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल कैपेसिटी से 1,496 मेगावाट (शुद्ध) थर्मल पावर की सप्लाई करेगा। वहीं, इसकी सहयोगी कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले में खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क से 5 गीगावाट (5,000 मेगावाट) सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगी।

बोली की शर्तों के अनुसार अदाणी ग्रीन एनर्जी पूरी आपूर्ति अवधि के दौरान 2.70 रुपये प्रति यूनिट की निश्चित लागत पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगी, जबकि कोयले से मिलने वाली बिजली कोयले की कीमतों के अनुसार होगी।

इंडिगो की मुंबई-दोहा फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान, एयरलाइन ने मांगी माफी

इंडिगो की मुंबई-दोहा फ्लाइट कई डिले होने के बाद रविवार को रद्द हो गई। इससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला। उड़ान 6E 1303 को 3 बजकर 55 मिनट पर टेक ऑफ करना था। लेकिन कई घंटों के डिले के बाद इसे कैंसल कर दिया गया।

नई दिल्ली। इंडिगो की मुंबई से दोहा जाने वाली फ्लाइट के यात्रियों को रविवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। विमान में कुछ तकनीकी समस्या हुई, जिसके चलते यात्रियों को चार घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत भी की कि फ्लाइट में देरी के चलते उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इस फ्लाइट को रविवार सुबह जल्दी उड़ान भरनी थी।

इंडिगो की फ्लाइट में क्या दिक्कत हुई?

इंडिगो एक आधिकारिक बयान जारी करके बताया कि मुंबई से दोहा के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E 1303 तकनीकी कारणों से डिले हुई। इंडिगो ने कहा, 'विमान ने कई बार अपने डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते उसमें काफी वक्त लगा और उसे आखिरकार रद्द करना पड़ा।'

इंडिगो ने असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उसकी एयरपोर्ट टीम ने प्रभावित ग्राहकों को तुरंत सहायता प्रदान की और जरूरी इंतजाम किया। वहीं, यात्रियों ने फ्लाइट लेट होने पर काफी नाराजगी जताई थी। कुछ ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन्हें न तो पानी मिला और न ही खाना। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस सख्त प्रतिक्रिया दी।

इंडिगो के साथ पहले भी समस्या

इंडिगो के साथ पिछले करीब एक हफ्ते में यह दूसरी दफा हुआ। इससे पहले 7 सितंबर को इंडिगो के एक विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी आ गई थी। इससे दिल्ली-वाराणसी फ्लाइट में सवार यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। इंडिगो ने इसके लिए भी माफी मांगी थी।

ईद मिलादुन्नबी जुलूस में बवाल, तिरंगे में चक्र की जगह लगाए चांद-तारे

राजस्थान में कोटा के अनंतपुरा और बिहार में सारण कोपा बाजार में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के त्योहार बारावफात पर सोमवार को निकाले गए जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वास्तिवक स्वरूप से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। झंडे के बीच चक्र की जगह इस्लामिक चिह्न चांद और तारे लगाए गए थे। चांद-तारे लगा तिरंगा लहराने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के पुलिस हरकत में आई।

नईदिल्ली: राजस्थान में कोटा के अनंतपुरा और बिहार में सारण कोपा बाजार में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के त्योहार बारावफात पर सोमवार को निकाले गए जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वास्तिवक स्वरूप से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। झंडे के बीच चक्र की जगह इस्लामिक चिह्न चांद और तारे लगाए गए थे। चांद-तारे लगा तिरंगा लहराने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के पुलिस हरकत में आई।

कोटा में पुलिस ने एक नाबालिग और सारण में दो लोगों रकीब पठान व मोहम्मद कैफ अंसारी को हिरासत में लिया है। जिस व्यक्ति ने ऐसा विवादित झंडा उपलब्ध कराया है, उसकी तलाश की जा रही है। उधर, उत्तर प्रदेश में आगरा सदर क्षेत्र स्थित राजपुर चुंगी में एक दोमंजिला घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लगाने की भी सूचना है।

धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई ठेस

इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

भारतीय ध्वज के साथ ऐसी छेड़खानी संविधान का उल्लंघन है।

हालांकि, पुलिस जब पहुंची, तब तक झंडा उतारा जा चुका था। वारां और शाहपुरा में जुलूस को लेकर विवाद - राजस्थान के दो अन्य जिलों बारां और शाहपुरा में बारावफात पर जुलूस को लेकर विवाद हुआ। बारां में मुस्लिम समाज के लोग तय मार्ग के स्थान पर दूसरे रास्ते से जुलूस निकालना चाहते थे। इसे लेकर उनका पुलिसकर्मियों के साथ लंबी बहस हुई। तनाव बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

मुस्लिम समाज के लोगों ने जताया विरोध

बाद में अधिकारियों के समझाने पर तय मार्ग पर जुलूस निकाला गया। शाहपुरा के जहाजपुर में जुलूस निकालने की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरकरार रखी।

यहां दो दिन पहले जलझुलनी एकादशी पर निकली यात्रा पर पथराव किया गया था। इसके बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है।

हिंदू समाज के लोगों ने घरों पर लगाई पट्टी

भीलवाड़ा में हिंदू समाज के लोगों ने घरों पर लगाई काली पट्टी भीलवाड़ा के सांगानेर में दो दिन पहले गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी के विरोध में सोमवार को हिंदू समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और घरों पर काली पट्टी लगाई। लोग अपने घर के दरवाजों पर ताला जड़कर गांव से दो किलोमीटर दूर मंदिर पर भजन-कीर्तन करने चले गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा आएंगे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 तारीख को ओडिशा आएंगे। प्रधानमंत्री का भुवनेश्वर आगमन से लेकर दिल्ली वापसी तक का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कल सुबह 10:50 बजे भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे।वहां से सीधे गड़कन बस्ती जायेंगे। प्रधानमंत्री 11 बजे गड़कन बस्ती पहुंचेंगे. बाद में प्रधानमंत्री 11.15 बजे से 11.45 बजे तक आवास लाभार्थियों से बात करेंगे। गदाकर से 11:45 बजे प्रस्थान कर 11:55 बजे जनता मैदान पहुंचेगी। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे तक वहीं रहेंगे। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की जाएंगी। जनता मैदान में कार्यक्रम के बाद ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री 11.20 को दिल्ली लौट जायेंगे। सुभद्रा का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री 17 को भुवनेश्वर आएंगे।

संस्कारशाला: सोशल मीडिया की दोस्ती - आज की दुनिया में एक नया आयाम

अंकुर

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे अगर सच्चाई और ईमानदारी से निभाया जाए, तो जीवन में खुशियों की बारिश कभी खत्म नहीं होती। लेकिन, आज के समय में दोस्ती ने एक नया रूप धारण कर लिया है। सोशल मीडिया के युग ने दोस्ती को नए आयाम दिए हैं, जहाँ हर कोई हजारों 'दोस्तों' से घिरा हुआ दिखता है, लेकिन हकीकत में वह भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कर सकता है।

पहले, दोस्ती की मिसाल दी जाती थी—"प्राण जाए, पर वचन न जाए।" दोस्त के लिए हर हाल में खड़े रहने का वादा होता था। पर आज, सोशल मीडिया की दोस्ती में यह प्रतिबद्धता कहीं खो सी गई है। जब चाहे किसी को 'फ्रेंड' बना लिया और जब मन किया, 'ब्लॉक' कर दिया। यह एक तरह से दोस्ती का व्यापार सा हो गया है—मूल्यों और भावनाओं के बिना।

दोस्ती का असली मतलब सिर्फ साथ में समय बिताना या बातें करना नहीं है, बल्कि एक-दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझना और उन्हें हल करने में मदद करना है। लेकिन आज की दोस्ती में यह गहराई कम ही देखने को मिलती है। सोशल मीडिया ने हमें ऐसे दोस्त दिए हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, और शायद मिलना भी न हो, लेकिन इन आभासी रिश्तों ने हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका दिया है।

दोस्ती अब किसी संख्या का हिस्सा बन गई है—कितने 'फ्रेंड्स', कितने 'फॉलोअर्स'। लेकिन यह दोस्ती नहीं, एक छलावा है। वास्तविक दोस्ती का अर्थ है कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो वह व्यक्ति हमारे साथ हो, भले ही वह कितनी भी दूर क्यों न हो।

इसलिए, इस भीड़भाड़ में, जहां हर कोई खुद को सोशल मीडिया पर व्यस्त दिखाने में लगा है, दोस्ती का असली मतलब वही है जो हमें अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलता था—समय देना, साथ बिताना, और एक-दूसरे की परवाह करना। दोस्ती का असली खजाना यह नहीं है कि कितने लोग आपके साथ हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों के साथ सच्चाई से खड़े हैं।

अंत में, यह समझना जरूरी है कि दोस्ती से बढ़कर अगर कुछ है, तो वह है आपका अपना समय। अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए, इस आभासी दुनिया से थोड़ा दूर होकर, सच्चे रिश्तों में समय लगाएं।

13 साल की बच्ची का अनोखा कारनामा, 800 किलो बाजरे से बनाई पीएम मोदी की फोटो

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्मान में 13 साल की एक छात्रा ने बेहद ही खास तस्वीर बनाई है। पीएम मोदी मिलेट्स (मोटे अनाज) को बढ़ावा देते हैं। इसे देखते हुए छात्रा ने 800 किलोग्राम मिलेट्स का इस्तेमाल कर उनकी तस्वीर (पोट्रेट) बनाई है। बच्ची ने लगातार 12 घंटे काम कर तस्वीर तैयार की। इससे एक नया विश्व रिकार्ड बना है।

चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्मान में 13 साल की एक छात्रा ने बेहद ही खास तस्वीर बनाई है। पीएम मोदी मिलेट्स (मोटे अनाज) को बढ़ावा देते हैं। इसे देखते हुए छात्रा ने 800 किलोग्राम मिलेट्स का इस्तेमाल कर उनकी तस्वीर (पोट्रेट) बनाई है।

बच्ची ने लगातार 12 घंटे काम कर तस्वीर तैयार की। इससे एक नया विश्व रिकार्ड बना है। बच्ची का नाम प्रेस्ली शेकिनाह है। छात्रा ने 17 सितंबर को नरेन्द्र मोदी के जन्मतिथि पर सम्मान देते हुए यह तस्वीर बनाई है।शेकिनाह चेन्नई के कोलपक्कम इलाके में रहने वाले प्रताप सेल्वम और संकीरानी (मां) की बेटी है।

800 किलो बाजरे का किया इस्तेमाल

प्रेस्ली चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती है। शेकिनाह ने 800 किलो बाजरे का इस्तेमाल करके 600 वर्ग फीट में पीएम मोदी की एक बड़ी तस्वीर बनाई है।

कृति अपने रिकॉर्ड में किया दर्ज

उसने सुबह साढ़े आठ बजे काम शुरू किया और रात साढ़े आठ बजे इसे पूरा किया। यूनिको वर्ल्ड रिकार्ड ने प्रेस्ली की इस कृति को अपने रिकार्ड में दर्ज किया है। इसे छात्र उपलब्धि श्रेणी के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। यूनिको वर्ल्ड रिकार्ड्स के निदेशक आर शिवरामन ने प्रेस्ली शेकिना को विश्व रिकार्ड प्रमाणपत्र और पदक से सम्मानित किया।

करमावास मालियन में समुद्र मंथन (संमन्द डोवन)

ब्यावर जिले की मोहरा कला ग्राम पंचायत में करमावास मालियन में समस्त 36 कोम समाज द्वारा समुद्र मंथन का प्रोग्राम प्रहलाद सिंह उदावत के सानिध्य में हुआ इसमें ढोल नगाड़े डी जे केसीट के संघ महिलाएं स्त्री कलश लेकर बड़े उत्साह के साथ पुरुष बाल गोपाल बड़े बुजुर्ग सभी नाचते गाते पूरे गांव की परिक्रमा शोभायात्रा निकाल कर उसके तथ पश्चात संमन्द डोवन के लिए बेरा रामसागर की नाडी पर एक साथ सम्मिलित होकर प्ररिक्रमा लगा करके प्रहलाद सिंह की तरफ से पूजा हवन करके सर्व प्रथम प्रहलाद सिंह के कर कमलों द्वारा समुद्र डोवन का प्रोग्राम शुरू हुआ इसमें सम्मिलित इन्द्रसिंह उदावत, लाल सिंह उदावत, प्रभु सिंह उदावत, प्रेम सिंह उदावत, रामलाल देवासी, ओम सिंह उदावत छैल सिंह उदावत, भरतसिह उदावत, भूपेंद्र सिंह , केशाराम प्रजापत, रूपाराम प्रजापत, धर्माराम प्रजापत लक्ष्मण राम प्रजापत, राजूराम, बाबूलाल प्रजापत, मानक रावरिया भंवरलाल प्रजापत, भूराराम सुथार, ओमप्रकाश सीरवी, राम सिंह राजपुरोहित, सभी सम्मिलित होकर समुन्द्र मंथन का प्रोग्राम संपन्न किया तत्पश्चात प्रसादी वितरण करके संपन्न हुआ।

2027 से पहले नहीं हो सकती जनगणना! कहां आ रही दिक्कत, सामने आई बड़ी वजह

2027 के फरवरी में व्यक्तियों की गणना का काम पूरा हो सकता है। जनगणना को दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में एक अप्रैल से 30 सितंबर तक घरों मवेशियों गाड़ियों और परिवारों के पास मौजूद अहम संसाधनों के आंकड़े जुटाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में अगले साल सात फरवरी से 28 फरवरी तक व्यक्तियों की गिनती शुरू होती है।

नई दिल्ली। तीन साल से विलंबित जनगणना 2027 से पहले होना मुश्किल नजर आ रही है। जनगणना के लिए 30 लाख कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और आंकड़े जुटाने के लिए इन कर्मियों के लिए टैब (इलेक्ट्रोनिक उपकरण) खरीदने की प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है।

जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षण

2021 की जनगणना की तैयारियों को देखें तो 2019 के अक्टूबर में ही मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण शुरू हो गया था। बाद में इन्हीं मास्टर ट्रेनर्स की मदद से 30 लाख जनगणनाकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना था, लेकिन पहले कोविड महामारी और फिर लगातार हो रहे चुनाव के कारण यह काम टलता गया।

किनते चरण में होती है जनगणना ?

जनगणना दो चरण में होती है। पहले चरण की जनगणना की शुरूआत एक अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी, दूसरा चरण सात फरवरी 2021 में होना था। 2019-20 के बजट में जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपये और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने के लिए 3,941 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

कब होगी भारत में जनगणना ?

जाहिर है यदि 2025-26 के बजट में जनगणना के लिए उचित बजटीय आवंटन होता है तो भी जनगणनाकर्मियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2025 जुलाई के बाद ही शुरू हो सकेगा। इसके बाद 2026 में एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पहले चरण में घरों की गणना हो सकती है। उसके बाद 2027 के फरवरी में व्यक्तियों की गणना का काम पूरा हो सकता है।

पहली बार कब हुई थी जनगणना ?

ऐसा नहीं है कि 1881 से हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना में पहली बार देरी हुई है। इसके पहले द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण 1941 की, चीन के साथ युद्ध के कारण 1961 की और पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण 1971 की जनगणना बाद में कराई गई थी।

नज़रें हैं बारिक

ज़ब सैनी को भी भाया था करनाल।
होना चाहते थे वह यहां के हो लाल।
हाँ अगर नहीं गली जो यहाँ पर दाल।
फ़रि भाजपा को ये भी रहेगा मलाल।
इसलिए अनिच्छा से बदल दी हैं सीट।
अब लाडवा में उन्हें कर दिया है फिट।
यहाँ मुख्यमंत्री अब भी है पसोंपेश में।
कब कैसे निकले लाडवा से जोश में?
उन्हें करना है पूरे हरियाणा का दौरा।
अब तो समय भी बचा है थोड़ा-थोड़ा।
निभाना है नब्बे प्रचार की जिम्मेदारी।
जीतेंगे छियालिस तभी होगी दमदारी।
भई जीतने का हुड्डा तो कर रहे हैं दावा।
पता नहीं किस-किसको होगा पछतावा।
अभी सभी रख रहे याद चुनाव तारीख।
तोल रहे सबको उनकी नज़रें हैं बारिक।
ज़ब सैनी को भी भाया था करनाल।
होना चाहते थे वह यहां के हो लाल।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

पुलिस, जांच एजेंसी या अदालत ... किसकी वजह से इंसाफ मिलने में होती है देरी?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के जमानत मामलों में मुकदमे में देरी और जांच में कमियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कहा कि लंबे समय तक आरोपियों का जेल में रहना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जांच एजेंसी अभियोजन पक्ष फोरेंसिक रिपोर्ट की देरी और अदालतों की लंबी प्रक्रियाओं के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली में देरी हो रही है।

नई दिल्ली। हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जमानत का निर्णय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी लंबे समय से जेल में है, किंतु अभी भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा अंतिम अभियोजन शिकायत या अंतिम आरोपपत्र दाखिल न किए जाने के कारण आरोपी जेल में ही रहता है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा शुरू नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि इससे आरोपित के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और इसलिए उसे जमानत दे दी गई।

आम धारणा यह है कि खराब जांच के कारण अपराधी मामलों में बरी हो जाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में केवल जांच एजेंसी ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें अभियोजन पक्ष, सीएफएसएल जैसी वैज्ञानिक सहायता प्रणाली, बचाव पक्ष के वकील, अदालतें और जेल भी शामिल हैं। ये सभी एजेंसियां (जेल को छोड़कर) किसी न किसी तरह से न्याय में देरी में योगदान देती हैं।

क्यों होती है न्याय में देरी ?

जांच एजेंसी में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण जांच अधिकारी पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे जांच में देरी होती है। थानों में तैनात पुलिस अधिकारी जांच करने के अलावा कानून-व्यवस्था प्रबंधन और इलाके में गश्त सहित कई अन्य काम भी करते हैं। जांच को कानून-व्यवस्था से अलग करने की जरूरत है। फोरेंसिक रिपोर्ट, साइबर फोरेंसिक और वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट आने में भी काफी समय लगता है, कभी-कभी दो से तीन साल तक लग जाते हैं। इन रिपोर्टों में देरी के कारण जांच को अंतिम रूप देने में देरी होती है। हमें निश्चित रूप से और अधिक प्रयोगशालाओं की जरूरत है।

सीमा पार जांच में बहुत समय लगता है। ऐसे मामलों में, लेटर्स रोगेटरी की प्रक्रिया के जरिए दूसरे राज्य या विदेश से सबूत हासिल किए जाते हैं। हालांकि, कई बार जवाब तीन से चार साल के अंतराल के बाद मिलता है।

न्यायपालिका और बचाव पक्ष के वकीलों की भूमिका

- विभिन्न अदालतों में 3.45 करोड़ (लगभग) आपराधिक मामले लंबित हैं। 16,694 जिला न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 5,300 न्यायाधीशों की कमी है। न्यायाधीशों की कमी के कारण लंबी तारीखें लगती हैं और इस तरह मुकदमों में देरी होती है।

वकीलों द्वारा बार-बार स्थगन मांगे जाने से न केवल मुकदमों में देरी होती है, बल्कि कई मामलों में यह खूंखार अपराधियों के लिए वरदान साबित होता है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग गवाहों को धमकाने में किया जाता है, जिससे उनका समझौता हो जाता है और आरोपी बरी हो जाता है।

समन प्रक्रिया सेवा प्रणाली धीमी है और अधिकांश बार गवाहों को अंतिम समय पर समन प्राप्त होता है, उस समय तक वे उस शहर में नहीं होते हैं, जहां उन्हें गवाही देनी होती है।

अदालतें कभी-कभी चल रही जांच के दौरान हस्तक्षेप करती हैं और स्थगन आदेश जारी करती हैं, जो अस्थाई रूप से जांच कार्यवाही को रोक देती हैं। आरोपी पक्षों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले ये हस्तक्षेप वर्षों तक खिंच सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट को संबंधित कानूनी मुद्दों को हल करने में समय लगता है।

नतीजतन, जांच एजेंसियों को अदालतों द्वारा स्थगन हटाने तक इंतजार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बीकानेर जमीन मामले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में महेश नागर नामक व्यक्ति ने 2019-20 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और परिणामस्वरूप मामले की जांच रुक गई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023